रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. [illegible]

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 5, 1970/अग्रहायण 14, 1892
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 5, 1970/AGRAHAYANA 14, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गए विधिक आदेश और अधिसूचनाएं।

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDERS

New Delhi, the 27th October 1970

S.O. 3812.—Whereas the Election Commission is satisfied that Dr. Mohammad Ayub, former resident of Vill. Dev, Tola Diwan Bigha, P.O. Dev, District Gaya and now resident of Village Ghoshpur, P. O. Kumra, District Purnia (West Bengal), a contesting candidate for mid-term election held in 1969 to the Bihar Legislative Assembly from Aurangabad Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by law as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Dr. Mohammad Ayub to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/243/69(122).]

भारत निर्वाचन आयोग

आदेशों

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर 1970

एस० ओ० 3812.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि बिहार विधान सभा के निर्वाचन के लिए औरंगाबाद निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार डा० मोहम्मद अयूब जो कि पहले ग्राम देव, टोला दिवान बिगहा, पो० देव, जिला गया के निवासी थे तथा जो अब ग्राम गोशपुर, पो० आ० कुमरा, जिला पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) के निवासी हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित विधि द्वारा विहित रीति में अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मोहम्द अयूब को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार–वि०स०/243/69(122)]

S.O. 3813.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Hemram, r/o Village Rajapur, P.O. Amrapara, District Santhal Parganas, Bihar, a contesting candidate for mid-term election to the Bihar Legislative Assembly held in February, 1969 from 142-Litipara (ST) Assembly Constituency has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Hemram, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/142/69(123.)]

एस० ओ० 3813.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि बिहार विधान सभा के लिए फरवरी, 1969 में हुए मध्यावधि निर्वाचन के लिए 142–लिटिपाड़ा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रामहेमराम निवासी ग्राम राजापुर, पो० आ० आमड़पाड़ा, जिला संथाल परगना, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित विहित रीति में अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, अत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा श्री रामहेमराम को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा

अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्रहित घोषित करता है ।

[स० बिहार–वि०स०/142/69(123)]

S.O. 3814.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhagat Murmu, r/o Village Rampur, P.O. Patharghatta, District Santhal Parganas, Bihar, a contesting candidate for mid-term election to the Bihar Legislative Assembly held in February, 1969 from 142-Litipara (ST) Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhagat Murmu, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/142/69(124).]

By Order,

ROSHAN LAL, Secy.

एस० ओ० 3814.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि बिहार विधान सभा के लिए फरवरी, 1969 में हुए मध्यावधि निर्वाचन के लिए 142–लिटिपाड़ा (आ०जा०जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भगत मुर्मू-निवासी ग्राम रामपुर, पो० आ० पथरघट्टा, जिला संताल परगना, लोक बिहार प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है ;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भगत मुर्मू को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्रहित घोषित करता है ।

[सं० बिहार–वि०सं०/142/69(124)]

आदेश से,

रोशन लाल, सचिव ।

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

New Delhi, the 18th November 1970

S.O. 3815.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 492 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), the Central Government hereby appoints Shri K. Ramaswamy, Advocate, Madras, as a Public Prosecutor for conducting the prosecution of the accused, in the case RC. 1/E/67-Madras in the original, appellate and revisional courts.

[No. 225/42/70-AVD(II)]

B. C. VANJANI, Under Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1970

एस० ओ० 3815—दंड प्रक्रिया संहिता 1898 (1898 का 5) की धारा 492 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री के० रामास्वामी, अधिवक्ता, मद्रास को मूल अपीलीय तथा पुनरीक्षण न्यायालयों में मामला आर० सी० 1/ई०/67—मद्रास, में, अभियक्तों के मुकदमें में कार्य संचालन के लिए, एतद्द्वारा लोक अभियोजक नियुक्त करती है ।

[सं० 225/42/70-ए०वी०डी० 2]

वी० सी० वंजानी,
अवर सचिव ।

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

New Delhi, the 11th November 1970

S.O. 3816.—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that, subject to his control and until further orders, the Administrator of the Union territory of Andaman and Nicobar Islands shall, in relation to that Union territory, exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Wakf Act, 1954 (29 of 1954).

[No. 4(7)/70-Waqf.]

E. VENKATESWARAN, Dy. Secy.

विधि मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1970.

एस० ओ० 3816—संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश करते हैं कि उनके नियंत्रण से तथा आगे आदेश होने तक, संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपों के प्रशासक, उस संघीय क्षेत्र के लिए, वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29) के अंतर्गत राज्य सरकार के रूप में शक्तियों का प्रयोग कर कार्यसंपादन करेंगे ।

[सं० 4(7)/70-वक्फ]

ई० वेंकटेशवरन, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

New Delhi, the 16th November 1970

S.O. 3817.—In pursuance of clause (a) of sb-section (1) read with sub-section (4) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby appoints Shri V. V. Chari as a Deputy Governor of the Reserve Bank of India for a period of five years from the date on which he takes over charge as Deputy Governor.

[No. F.3(38)-BC/70.]

वित्त मंत्रालय

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 16 नम्बर, 1970

एस० ओ० 3817.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का दूसरा) की धारा 8 की उप-धारा (4) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (क) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री वी० वी० चारी को भारतीय रिजर्व बैंक का पांच वर्ष की अवधि के लिये उस दिन से उप-गवर्नर नियुक्त करती है जिस दिन से वे इस पद का कार्य भार ग्रहण करेंगे ।

[सं० एफ० 3(38)-बी० फी०/70]

S.O. 3818.—In pursuance of clause (a) of sub-section (1) read with sub-section (4) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby appoints Shri S. S. Shiralkar as a Deputy Governor of the Reserve Bank of India for a period of five years from the date on which he takes over charge as Deputy Governor.

[No. F.3(38)-BC/70.]

K. RAMAMURTHY, Jt. Secy.

एस० ओ० 3818—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का दूसरा) की धारा 8 की उप-धारा (4) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (क) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा श्री एस० ए० शिरालकर को भारतीय रिजर्व बैंक का पांच वर्ष की अवधि के लिए उस दिन से उप-गवर्नर नियुक्त करती है जिस दिन से वे इस पद का कार्य भार ग्रहण करेंगे ।

[सं० एफ० 3(38)-बी० सी० 70]

के० राममूर्ति, संयुक्त सचिव ।

(Department of Banking)

New Delhi, the 20th November 1970

S.O. 3819.—Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 6th November, 1970.

BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	47,63,44,000
		Rupee Coin	3,71,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	5,81,000
		Bills Purchased and Discounted:—	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	172,00,00,000	(a) Internal	..
		(b) External	..
		(c) Government Treasury Bills	6,45,19,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	37,00,00,000	Balances Held Abroad*	127,08,87,000
		Investments**	88,03,56,000
		Loans and Advances to:—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	95,00,00,000	(i) Central Government	..
		(ii) State Governments @	151,73,83,000
		Loans and Advances to :—	
		(i) Scheduled Commercial Banks†	153,26,00,000
Deposits:—		(ii) State Co-operative Banks††	274,44,37,000
(a) Government—		(iii) Others	2,55,50,000
(i) Central Government	83,76,37,000		
(ii) State Governments	18,45,81,000		

		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund —	
(b) Banks—		(a) Loans and Advances to:—	
(i) Scheduled Commercial Banks . . .	180,95,98,000	(i) State Governments	34,37,52,000
		(ii) State Co-operative Banks	21,48,84,000
(ii) Scheduled State Co-operative Banks . .	7,70,2),000	(iii) Central Land Mortgage Banks	..
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks .	81,09,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	9,57,02,000
(iv) Other Banks	2),53,000	Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund —	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks . .	5,52,23,000
(c) Others	118,87,98,000	Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund —	
Bills Payable	46,81,44,000	(a) Loans and Advances to the Development Bank .	26,26,71,000
Other Liabilities	64,33,93,000	(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
		Other Assets	32,49,82,000
Rupees .	981,02,42,000	Rupees . .	981,02,42,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

†Includes Rs. 72,26,25,000/- advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural (Credit Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 11th day of November, 1970.

An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 6th day of November 1970

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	47,63,44,000		Gold Coin and Bullion:—		
			(a) Held in India	182,53,11,000	
Notes in circulation	3991,01,04,000		(b) Held outside India	..	
			Foreign Securities	366,42,00,000	
Total Notes issued		4038,64,48,000	TOTAL		548,95,11,000
			Rupee Coin		57,36,62,000
			Government of India Rupee Securities		3432,32,75,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
TOTAL LIABILITIES		4038,64,48,000	TOTAL ASSETS		4038,64,48,000

Dated the 11th day of November, 1970.

S. JAGANNATHAN,
Governor.

[No. F.3(3)-BC/70].

(बैंकिंग विभाग)

एस० ओ० 3819.—6 नवम्बर, 1970 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1970

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी	5,00,00,000	नोट	47,63,44,000
आरक्षित निधि	1,50,00,00,000	रुपये का सिक्का	3,71,000
		छोटा सिक्का	5,81,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण		खरीदे और भुनाये गये बिल :—	
(दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि . . .	172,00,00,000		
राष्ट्रीय कृषि ऋण		(क) देशी	..
(स्थिरीकरण) निधि . . .	37,00,00,000	(ख) विदेशी	..
		(ग) सरकारी खजाना बिल . .	6,45,19,000
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण		विदेशों में रखा हुआ बकाया* . .	127,08,87,000
(दीर्घ कालीन क्रियाएं) निधि . .	95,00,00,000	निवेश**	88,03,56,000
जमा राशियां :—		ऋण और अग्रिम :—	
(क) सरकारी		(i) केन्द्रीय सरकार को . .	..
(i) केन्द्रीय सरकार . . .	83,76,37,000	(ii) राज्य सरकारों को@ . .	151,73,83,000
(ii) राज्य सरकारें . . .	18,45,81,000		
		ऋण और अग्रिम :—	
(ख) बैंक		(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को† .	153,26,00,000
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक . .	180,95,98,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को†† . .	274,44,37,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक .	7,70,29,000	(iii) दूसरों को . . .	2,55,50,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
		(क) ऋण और अग्रिम :—	
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक .	81,09,000	(i) राज्य सरकारों को . . .	34,37,52,000
(iv) अन्य बैंक . . .	†29,53,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को . .	21,48,84,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को . .	. .
(ग) अन्य . . .	118,87,98,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम :—	9,57,02,000
देय बिल . . .	46,81,44,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम .	†5,52,23,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :—	
अन्य देयताएं	64,33,93,000	(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	26,26,71,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	. .
		अन्य आस्तियां	32,49,82,000
रुपये	981,02,42,000	रुपये	981,02,42,000

*नकदी, अवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

†रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 (4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंको को मियादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 72,26,25,000 रु० शामिल हैं।

††राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

तारीख : 11 नवम्बर, 1970

रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में नवम्बर, 1970 की 6 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिये लेखा

इशू विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट . .	47,63,44,000		सोने का सिक्का और बुलियन :—		
संचलन में नोट	3991,01,04,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,53,11,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ . .	..	
जारी किए गए कुल नोट		4038,64,48,000	विदेशी प्रतिभूतियां	366,42,00,000	
			जोड़ . .		548,95,11,000
			रुपये का सिक्का		57,36,62,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां		3432,32,75,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र .		..
कुल देयताएं . .		4038,64,48,000	कुल आस्तियां .		4038,64,48,000

तारीख 11 नवम्बर, 1970

एस० जगन्नाथन,
गवर्नर ।

[सं० एफ० 3(3)-बी० सी०/70]

New Delhi, the 23rd November 1970

S.O. 3820.—Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, as on the 13th November, 1970

BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	14,21,08,000
		Rupee Coin	3,22,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	6,03,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	172,00,00,000	Bills Purchased and Discounted :—	
		(*a*) Internal	..
		(*b*) External	..
		(*c*) Government Treasury Bills	19,76,42,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	37,00,00,000	Balances Held Abroad*	111,88,72,000
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	95,00,00,000	Investments**	107,06,01,000
		Loans and Advances to :—	
		(*i*) Central Government	..
		(*ii*) State Governments @	157,92,67,000
Deposits :—		Loans and Advances to :—	
		(*i*) Scheduled Commercial Banks†	145,37,65,000
		(*ii*) State Co-operative Banks††	276,05,22,000
(a) Government :—		(*iii*) Others	1,70,25,000
(*i*) Central Government	85,67,00,000		

		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund—	
(ii) State Governments	4,92,54,000	(a) Loans and Advances to :—	
		(i) State Governments	34,37,42,000
		(ii) State Co-operative Banks	21,44,17,000
		(iii) Central Land Mortgage Banks	..
(b) Banks—		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	9,57,02,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund—	
(i) Scheduled Commercial Banks	185,41,68,000		
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	7,53,23,000	Loans and Advances to State Co-operative Banks	5,45,93,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	81,07,000		
(iv) Other Banks	32,03,000	Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund—	
(c) Others	109,54,42,000	(a) Loans and Advances to the Development Bank	26,26,71,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	
Bills payable	43,69,18,000		
Other Liabilities	66,74,32,000	Other Assets	32,46,95,000
Rupees	963,65,47,000	Rupees	963,65,47,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary over-drafts to State Governments.

†Includes Rs. 59,81,25,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 18th day of November 1970.

An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 13th day of November, 1970.

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	14,21,08,000		Gold Coin and Bullion :—		
			(a) Held in India . . .	182,53,11,000	
Notes in circulation . . .	4023,26,03,000		(b) Held outside India . .	..	
Total Notes issued . . .		4037,47,11,000	Foreign Securities . . .	386,42,00,000	
			TOTAL		568,95,11,000
			Rupee Coin		56,19,22,000
			Government of India Rupee Securities		3412,32,78,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper . . .		..
TOTAL LIABILITIES .		4037,47,11,000	TOTAL ASSETS . . .		4037,47,11,000

Dated the 18th day of November, 1970.

(Sd.) S. JAGANNATHAN
Governor.

[No. F. 3 (3)-BC/70.]

K. YESURATNAM, Under Secy

CORRIGENDUM

In the statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking, Department as on 18th September 1970 published on pages Nos. 4801-2 of Part II, Section 3(ii) of the Gazette of India issue dated 24th October 1970, the figure against the head "Investments" on the assets side of the statement should be read as 96,84,37,000 instead of 92,84,37,000.

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1970

एस० ओ० 3820.—13 नवम्बर, 1970 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण ।

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी . . .	5,00,00,000	नोट . . .	14,21,08,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का . . .	3,22,000
		छोटा सिक्का . .	6,03,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण		खरीदे और भुनाये गये बिल:—	
(दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि . . .	172,00,00,000		
राष्ट्रीय कृषि ऋण		(क) देशी	. .
(स्थिरीकरण) निधि . .	37,00,00,000	(ख) विदेशी . . .	. .
		(ग) सरकारी खजाना बिल . .	19,76,42,000
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण		विदेशों में रखा हुआ बकाया* . .	111,88,72,000
(दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि . . .	95,00,00,000	निवेश** . .	107,06,01,000
जमा-राशियां :—		ऋण और अग्रिम :—	
(क) सरकारी		(i) केन्द्रीय सरकार को . . .	. .
(i) केन्द्रीय सरकार . . .	85,67,00,000	(ii) राज्य सरकारों को@ . .	157,92,67,000
(ii) राज्य सरकार . .	4,92,54,000		
		ऋण और अग्रिम :—	
(ख) बैंक		(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को† . .	145,37,65,000
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक . .	185,41,68,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को†† . .	276,05,22,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक . .	7,53,23,000	(iii) दूसरों को . .	1,70,25,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
		(क) ऋण और अग्रिम :–	
(iii) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक .	81,07,000	(i) राज्य सरकारों को . . .	34,37,42,000
(iv) अन्य बैंक . . .	32,03,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को . .	21,44,17,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को . .	..
(ग) अन्य .	109,54,42,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	9,57,02,000
देय बिल . . .	43,69,18,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम .	5,45,93,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :–	
अन्य देयताएं . . .	66,74,32,000	(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम .	26,26,71,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किए गए बांडों/डिबेंचरों में निवेश	..
		अन्य आस्तियां . . .	32,46,95,000
रुपये	963,65,47,000	रुपये	963,65,47,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं ।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किए गए निवेश शामिल नहीं हैं ।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं ।

†रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम की धारा 17(4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मियादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 59,81,25,000 रुपये शामिल हैं ।

††राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं ।

तारीख : 18 नवम्बर, 1970 ।

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में नवम्बर, 1970 की 13 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिये लेखा

इशू विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए —			सोने का सिक्का और बुलियन:—		
नोट	14,21,08,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,53,11,000	
संचलन में नोट	4023,26,03,000		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	..	
			विदेशी प्रतिभूतियां	386,42,00,000	
जारी किए गए कुल नोट		4037,47,11,000			
			जोड़		568,95,11,000
			रुपये का सिक्का		56,19,22,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां		3412,32,78,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र		..
कुल देयताएं		4037,47,11,000	कुल आस्तियां		4037,47,11,000

तारीख 18 नवम्बर, 1970।

एस० जगन्नाथन,
गवर्नर ।

[सं० एफ० 3 (3)—बी० सी०/70]

के० येसूरत्नम, अनु-सचिव ।

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS AND MINES & METALS

(Department of Mines and Metals)

New Delhi the 16th November 1970

S.O. 3821.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan of the area covered by this notification can be inspected in the Office of the National Coal Development Corporation Limited, (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi or in the Office of the Collector Sahdol (MP) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the land mentioned in the said Schedule shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer of the National Coal Development Corporation Limited, Darbhanga House, Ranchi, within 90 days from the date of publication of this notification.

SCHEDULE

(Sohagpur Block V—Extension No. 1)

(Sohagpur coalfield)

Drg. No. Rev/7/69.
Dated 20-6-1969.
(Area notified for prospecting)

Sl. No.	Village	Tehsil	District	Area	Remarks
1	Pasan . .	Sohagpur	Sahdol	..	Part.

Total area: 56·00 acres (Approximately)
or 22·68 Hectares (approximately)

Boundary Description:

A-B Line passes through village Pasan and meets at point 'B'.

B-C. Line passes through village Pasan (which is the part common boundary of Sub-Block-III Mining Rights area of Sohagpur Block-V acquired u/s 9(1) of the Coal Act vide S.O. No. 2974 dated 4th December, 1961) and meets at point 'C'.

C-A. Line passes through village Pasan (which is the part common boundary of Sub-Block-III Mining Rights area of Sohagpur Block-V acquired u/s 9(1) of the Coal Act *vide* S.O. No. 2974 dated 4th December, 1961) and meets at starting point 'A'.

[No. F. C3-1(2)/70.]

पेट्रोलियम तथा रसायन तथा खान तथा धातु मंत्रालय

(खान तथा धातु विभाग)

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1970

का० आ० 3821.—यतः केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमियों में से कोयला अभिप्राप्त होने की संभावना है ;

अतः, अब, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उसमें कोयला के लिए पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले श्रेत्र के रेखाओं का निरीक्षण राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), दरभंगा हाउस, रांची के कार्यालय में अथवा नियंत्रक, शाहडोल (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक, 1, कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है ।

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्देशित समस्त मानचित्र, चार्ट और अन्य दस्तावेज, इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के अन्दर राजस्व आफिसर, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची को परिदत्त करेंगे ।

अनुसूची

(सोहागपुर खण्ड 5—विस्तार संख्या 1)

ड्राइंग संख्या राजस्व/7/69
तारीख 20-6-1969
(पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित क्षेत्र)

सोहागपुर कोयला क्षेत्र

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1	पासन	सोहागपुर	शाहडोल	—	भाग
			कुल क्षेत्र : 56.00 एकड़ (लगभग) या 22.68 हैक्टेयर (लगभग)		

सीमा वर्णन

क—ख— लाइन ग्राम पासन से गुजरती है और 'ख' बिन्दु पर मिलती है ।

ख—ग— लाइन ग्राम पासन से गुजरती है (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन का० आ० सं० 2974 तारीख 4-12-61 द्वारा अंकित सोहागपुर खण्ड 5 के उप खंड-III खनन अधिकार क्षेत्र की भागता सामान्य सीमा है) और बिन्दु 'ग' पर मिलती है ।

ग—क— लाइन ग्राम पासन से गुजरती है (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन का आ० सं० 2974 तारीख 4-12-61 द्वारा अंकित सोहागपुर ख ड 5 के उप खंड—III खनन अधिकार क्षेत्र की भागता सामान्य सीमा है) और प्रारम्भिक बिन्दु 'क' पर मिलती है ।

[सं० एफ० सी० 3-1(2)/70]

S.O. 3822.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred, by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan of the area covered by this notification can be inspected at the office of the National Coal Development Corporation Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi or at the office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh (Bihar) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the lands mentioned in the said Schedule shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer of the National Coal Development Corporation Limited, Darbhanga House, Ranchi within ninety days from the date of publication of this notification.

SCHEDULE

Bokaro Block-I (Sawang Extension)

(East Bokaro Coalfield)

Drg. No. Rev/6/70
Dated 29-4-70

(Showing lands notified for prospecting)

Sl. No.	Village	Thana	Thana No.	District	Area	Remarks
1	Sowang	Gumla	107	Hazaribagh		Part
2	Gobindpur	Nawadih (Bermo)	15	"		"
3	Armo	"	11	"		"

Total area : 295·00 acreas (approximately)
or 119·48 hectares (approximately)

Boundary Description:—

A-B. line passes through Kunar River in village Armo and meets at point 'B'.

B-C. line passes along the part common boundary of villages Sasbera and Sawang and meets at point 'C'.

C-D. line passes though village Sawang and meets at point 'D'.

D-E-F-G. lines pass through villages Sawang and Gobindpur and meet at point 'G'.

G-H-A. lines pass along the left bank of River Kunar in villages Gobindpur and Armo and meet at point 'A'.

[No. F. C 3-1(11)/70.]

K. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

का० आ० 3822.—यत : केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमियों में से कोयला अभिप्राप्त होने की संभावना है ।

अतः, अब, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उसमें कोयले के लिए पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखाओं का निरीक्षण, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), दरभंगा हाउस, रांची के कार्यालय में अथवा उपायुक्त, हजारी बाग (बिहार) के कार्यालय में, अथवा कोयला नियंत्रक, 1, कांउसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है ।

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमियों में हितबद्ध सभी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्देशित समस्त मानचित्र, चार्ट और अन्य दस्तावेज, इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के अन्दर राजस्व आफिसर, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची को परिदत्त करेंगे।

अनुसूची

बोकारो खंड—1 (स्वैंग विस्तार)

(पूर्वीय बोकारो कोयला क्षेत्र)

ड्राइंग सं० राजस्व/6/70

तारीख 29-4-70

(पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि को दर्शित करने वाली)

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला क्षेत्र	टिप्पणियां
1	सवैंग	गुमिया	107	हजारीबाग	भाग
2	गोबिन्दपुर	नवादिह (बर्मो)	15	,,	,,
3	आर्मो	,,	11	,,	,,

कुल क्षेत्र : 295.00 एकड़ (लगभग) ।
अथवा 119.48 हेक्टेयर (लगभग)

सीमा वर्णन :

क–ख– लाइन ग्राम आर्मो में कुनार नदी से होकर गुजरती है और 'ख' बिन्दु पर मिलती है ।

ख–ग– लाइन ससबेरा और सवैंग ग्रामों की भागतः सामान्य सीमा से होकर गुजरती है और 'ग' बिन्दु पर मिलती है ।

ग–घ– लाइन ग्राम सवैंग से होकर गुजरती है और 'घ' बिन्दु पर मिलती है ।

घ–ङ–च–छ लाइनें ग्राम सवैंग और गोबिन्दपुर से होकर गुजरती हैं और 'छ' बिन्दु पर मिलती हैं ।

छ–ज–क– लाइनें गोबिन्दपुर और आर्मो ग्रामों में कुनार नदी के बाएं तट से होकर गुजरती हैं और 'क' बिन्दु पर मिलती हैं ।

[सं० एफ० सी-3-1(11)/70]

के० सुब्रामण्यन, अवर सचिव ।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDER

New Delhi, the 16th November 1970

S.O 3823—In pursuance of the directions issued under the provisions of each of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in Gujarati to be of the description specified against each in column 6 of the said second schedule.

The first Schedule

(1) Sub-Section 4 of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).

(2) Sub-Section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XVII of 1953).

(3) Sub-Section (4) of Section 5 and Section 9 of the Saurashtra Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Saurashtra Act XVII of 1953).

The Second Schedule

S. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news & current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1.	Mahitichitra No. 126	213.36M	Director of Information, Government of Gujarat Sachivalaya, Ahmedabad-15		Film dealing with news and current events (For release in Gujarat Circuit only).
2.	Mahitichitra No. 130	243·84 M	Do.		Do.

[No. F. 28/1/70-FP App.1519]

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

आदेशों

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1970

एस० ओ० 3823—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके गुजराती भाषा रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

(1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37 वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 1 की उपधारा (4) तथा धारा 16।

(2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 17 वां बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9।

(3) सौराष्ट्र सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 17वां सौराष्ट्र अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (4) तथा धारा 9।

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमैन्ट्री फिल्म है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	महितिचित्रा संख्या 126	21336 मीटर	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार सचिवालय, अहमदाबाद।		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल गुजरात सर्किट के लिये
(2)	महितिचित्रा संख्या 130	2±384 मीटर	—तथैव—		—तथैव—

[सं० फा० 28/1/70-एफ० पी० परिशिष्ट 1519]

S.O. 3824.—In pursuance of the directions issued under the provisions of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in all their language versions to be of the description specified against each in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-Section (4) of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).

(2) Sub-Section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XI of 1953).

The Second Schedule

S. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news & current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1.	Maharashtra News No. 218	192·94 M	Director of Publicity, Govt. of Maharashtra, 68 Film Centre, Tardeo Road, Bombay-34.		Film dealing with news and current events (For release in Maharashtra Circuit only).
2.	Bhagyalaxmi (Maharashtra Lottery)	304·80 M	Shri B. P. Srivastava, M/s Seven Arts Advertising, 6/7th Floor, Tardeo Airconditioned Market, Bombay-34.		Film dealing with news and current events (For release in Maharashtra Circuit only).

[No. F. 28/1/70-FP App. 1520]

K. K. KHAN, Under Secy.

एस० ओ० 3824 इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भाषाओं के रूपान्तरों सहित जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

(1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16.

(2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 11वां बम्बई अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9.

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमैन्ट्री फिल्म है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	महाराष्ट्र समाचार संख्या 218	192·94 मीटर	प्रचार निदेशक, महाराष्ट्र सरकार 68, फिल्म सैन्टर, तारदेव रोड, बम्बई-34		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल महाराष्ट्र सर्किट के लिये)
(2)	भाग्यलक्ष्मी (महाराष्ट्र लाटरी)	30480 मीटर	श्री श्री पी सिरीवास्तवा, मैसर्ज सैवन आर्ट्स ऐडवरटाइजिंग, 6/7 तल. तारदेव एयरकंडीशंड मार्केट, बम्बई 34.		—तथैव—

[सं० फा० 28/1/70-एफ० पी० परिशिष्ट 1520]

क० क० खान, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Internal Trade)

New Delhi, the 6th October 1970

S.O. 3825.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 the Central Government hereby appoints Shri E. K. Vasudevan, as Member of the Forward Markets Commission, Bombay, *vice* Prof. S. V. Kogekar, granted leave with effect from the 12th October, 1970 to the 21st November, 1970.

[No. 17(5)-I.T./70.]

R. C. SETHI, Dy. Secy.

औद्योगिक विकास विभाग तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(आंतरिक व्यापार विभाग)

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 1970

एस० ओ० 3825—अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के खंड 3 के उपखंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री ई० के० वसुदेवन को प्रो० एस० वी० कोजकर, जिन्हें 12 अक्तूबर, 1970 से 21 नवम्बर, 1970 तक छुट्टी स्वीकृत की गई है, के स्थान पर एतद् द्वारा वायदा बाजार आयोग का सदस्य नियुक्त करती है।

[सं 17(5)-आई० टी०/70]

आर० सी० सेठी, उप सचिव।

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 10th November 1970

S.O. 3826/IDRA/6/5.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with Rules 2, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952 and in continuation of the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 1906/IDRA/6/5 dated the 8th May, 1970, the Central Government hereby make the following change in the composition of the Development Council for Instruments Industry.

Shri S. SOMASUNDARAM, Department of Atomic Energy, C.S.M. Marg, BOMBAY-1.	Member *Vice* Shri A. PARTHASARTHI

[No. LFI(A)-3(5)/66.]

C. MALLIKARJUNAN, Under Secy.

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1970

एस० ओ० 3826/आई० डी० आर० ए०/6/5.—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विकास परिषदें

(कार्यविधि) नियम, 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पढ़ते हुए, तथा भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० एस० ओ० 1906 आई० डी० आर० ए/6/5 दिनांक 8 मई, 1970 को जारी रखते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यंत्र उद्योग की विकास परिषद् की रचना में निम्नलिखित परिवर्तन करती है :—

श्री एस० सोमसुन्दरम, अणु-शक्ति विभाग, सी० एस० एम० मार्ग, बम्बई–1	श्री ए० पार्थसारथी के स्थान पर सदस्य।

[सं एल० ई० आई० (ए)–3(5)/66]

सी० मल्लिका नुर्नन,

अवर सचिव।

(Department of Industrial Development)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 9 November, 1970

S.O. 3827:—In exercise of the powers conferred on me under sub-regulation (4) of regulation 3 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended from time to time, modifications to the provisions of the Indian Standards, details of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have tentatively been made with a view to expediting the use of the Standard Mark, without in any way affecting the quality of goods covered by the relevant standard. This notification shall come into force with immediate effect :

THE SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of Indian Standard, the Provisions of which have been Modified	Number of the Existing Clause Affected	Particulars of the Modifications made to the Provisions of the Indian Standard
1	2	3	4
1	IS:10-1964 Specification for plywood tea-chests (*Second revision*)	Clause 5·1·1	(*Page* 9, *Clause* 5·1·1) Substitute the following for the existing clause: "5·1·1 Any other sizes as agreed to between the manufacturer and the purchaser shall be permitted; provided that for sizes larger than those given in 5·1 the requirements of end compression test and corner drop test (*see* 9) specified for 48×48×60 cm size are met with."

[No CMD/13 : 4]

DR. A. N. GHOSH,
Director General.

(औद्योगिक विकास विभाग)

(भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1970

एस० ओ० 3827—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 3 के उपविनियम (4) के अधीन प्राप्त शक्तियों के आधार पर मानक चिह्न लगाने में गति लाने के उद्देश्य से भारतीय मानक में कुछ परिवर्तन परीक्षार्थ रूप में किया गया है, जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए हैं। इस परिवर्तन से तत्सम्बन्धी भारतीय मानक के अधीन माल की किस्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह परिवर्तन तुरन्त ही लागू हो जाएगा।

अनुसूची

क्रमांक	भारतीय मानक की पद-संख्या और शीर्षक जिसके उपबंधों का संशोधन हुआ है	संशोधित वर्तमान खण्डों की संख्या	उपबंधों में किए गए परिवर्तनों के विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	IS : 10-1964 की चाय की पेटियों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	प्लाईवुड, खण्ड 5.1.1	(पृ0 9 खण्ड 5.1.1) वर्तमान खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित कर लीजिए : "5.1.1 ग्राहक और विक्रेता के बीच सहमत अन्य आकार भी अनुमत हो सकते हैं बशर्ते कि 5.1 में दिए आकार से बड़े आकार वाली पेटियां 48×48×60 सेमी आकार के लिए निर्धारित कोना संपीड़न परीक्षण और कोने के बल गिराए जाने के परीक्षण (देखिए 9) सम्बन्धी अपेक्षाओं के अनुरूप हों।

[सं० सी० एम० डी०/13:4]

(डा०) ए० एन० घोष,
महानिदेशक।

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(Directorate General of Shipping)

MERCHANT SHIPPING

Bombay, the 8th September, 1970

S.O. 3828.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 8 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), read with the order of the Government of India in the late Ministry of Transport and Communications No. S.O. 771, dated the 7th March, 1962 and in supersession of the Notification No. S.O. 1353, dated the 1st April, 1969, the Director General of Shipping hereby appoints the officers mentioned in the second Column of the Schedule annexed hereto as the officers who shall be in-charge of the office of the Mercantile Marine Department at the Port of Marmugao for the periods mentioned against their names in Column 3 thereof.

SCHEDULE

Sr.	Name of Surveyor	Period
1.	Shri R. G. Singh Engineer and Ship Surveyor	14th August, 1970 to 19th August, 1970.
2.	Shri J. S. Gill Natural Surveyor	20th August, 1970 until further orders.

2. This Notification shall be deemed to have come into force on the 14th day of August, 1970.

[No. F. 132-SH(52)/61.]

R. DORAISWAMY,
Director General of Shipping.

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय

पो परिवहन महानिदेशालय

(व्यापारिक पोतपरिवहन)

बम्बई, 8 सितम्बर, 1970

का०आ० 3828—भूतपूर्व परिवहन तथा संचार मंत्रालय सं० का० आ० 771 दिनांक 7 मार्च, 1962 के साथ पठित व्यापारिक पोतपरिवहन अधिनियम 1958 (1958 के 44) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा अधिसूचना सं० का० आ० 1353 दिनांक 1 अप्रैल, 1969 के अधिक्रमण में पोतपरिवहन महानिदेशक एतद्द्वारा इस अधिसूचना के साथ अनुबंधित अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में दिये गये अधिकारियों को उक्त अनुसूची के स्तम्भ में उनके सामने दी गयी अवधियों के लिये ऐसे अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं जो मारमुगाओं पत्तन पर जल परिवहन विभाग के कार्यालय के कार्यभारी होंगे ।

अनुसूची

क्रम संख्या	सर्वेक्षक का नाम	अवधि
1.	श्री आर० जी० सिंह इंजीनियर तथा पोत सर्वेक्षक	14 अगस्त, 1970 से 19 अगस्त, 1970 तक
2.	श्री जे० एस० गिल नौ सर्वेक्षक	20 अगस्त, 1970 से अगला आदेश होने तक ।

2. यह अधिसूचना अगस्त, 1970 के 14वें दिन से लागू समझा जायेगा ।

[सं० 132–एस एच (52)/61]

आर० दोरायस्वामी,
पोतपरिवहन महानिदेशक ।

(Transport Wing)

New Delhi, the 20th November 1970

S.O. 3829.—In pursuance of rule 5 of the Indian Merchant Shipping (Seamen's Employment Office, Calcutta) Rules, 1954, the Central Government hereby appoints a Seamen's Employment Board (Home Trade) at the port of Calcutta for a period of two years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette consisting of the following members, namely:—

1. Deputy Director General of Shipping, incharge of Seamen's Employment Offices.—*Chairman.*
2. Director, Seamen's Employment Office, Calcutta.—*Member Secretary.*
3. Shri M. K. Tanna,— } *Members representing shipowners.*
4. Capt. C. G. Bhoot. }
5. Shri Bejoy Kumar Mukherjee } *Members representing seamen.*
6. Shri Sudhangsu Sen }

[No. 15-MT(5)/70.]

HARBANS SINGH, Dy. Secy.

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली 20 नवम्बर, 1970

एस० ओ० 3829.—भारतीय व्यापार पोतपरिवहन (नाविक रोजगार कार्यालय, कलकत्ता) नियमावली, 1954 के नियम 5 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कलकत्ता पत्तन पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये एक नाविक रोजगार बोर्ड (गृह व्यापार) नियुक्त करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. पोतपरिवहन के उप महानिदेशक, नाविक रोजगार कार्यालयों के कार्यकारी —अध्यक्ष
2. निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय, कलकत्ता । सदस्य सचिव

3. श्री एम० के० तन्ना
4. कप्तान सी० जी० भूट — पोतमालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ।
5. श्री विजय कुमार मुकरजी
6. श्री सुधांगसू सेन — नाविकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

[सं 15-एम०टी०(5)/70]

हरबन्स सिंह, उप सचिव ।

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 4th November 1970

S.O. 3830.—In pursuance of rule 6 of the Export of Frog Legs (Inspection) Rules, 1965, the Central Government hereby appoints the Director, Haffkine Institute, Bombay, as member of the panel of experts constituted for Bombay Region, for the purpose of hearing appeals under the said rule against the decision of the Export Inspection Agency-Bombay, and directs that the following amendments shall be made to the notification of the Government of India in the late

Ministry of Foreign Trade and Supply (Department of Foreign Trade) No. S.O. 3323, dated the 14th August, 1969, namely:—

In column (2) of the Table appearing below the said notification:—

(1) Under the heading "Cochin Region (covering the States of Kerala, Mysore and the Union Territories of the Laccadives, Minicoy and Amindivi Islands)," for item 8 the following item shall be substituted, namely:—

"8. The Deputy Chief Executive, Export Inspection Agency-Cochin, Manohar Building, M.G. Road, Ernakulam, Cochin-11-*Ex-officio* Convener."

(2) Under the heading "Bombay Region (covering the States of Maharashtra, Gujarat and the Union Territories of Goa, Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli)," for items 5, 6 and 7, the following items shall be substituted, namely:—

"5. The Administrator, Maharashtra Rajya Machimar Sahakari Sangha Ltd., 3, Mahatma Phule Fish Market, Bombay.

6. The Director, Haffkine Institute, Old Government House, Bombay-12.

7. The Deputy Chief Executive, Export Inspection Agency-Bombay, 11/21, Mathew Road (2nd floor), Bombay-4—*Ex-officio* Convener."

(3) Under the heading "Madras Region (covering the States of Andhra Pradesh, Tamilnadu and the Union Territory of Pondicherry)," for item 6, the following item shall be substituted, namely:—

"6. The Deputy Director Export Inspection Agency, Madras, 123, Mount Road, Madras-6—*Ex-officio* Convener."

[No. 60(39)/Exp. Insp./67.]

विदेशी व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1970

का० आ० 3830—मेढक की टांगों का निर्यात (नियंत्रण) नियम, 1965 के नियम 6 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेशक, हाफकिन इन्स्टीट्यूट, मुम्बई को निर्यात निरीक्षण अधिकरण-मुम्बई के विनिश्चय के विरुद्ध उक्त नियम के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिए मुम्बई क्षेत्र के लिए गठित विशेषज्ञों के पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और निदेश देती है कि भारत सरकार के भूतपूर्व विदेशी व्यापार और आपूर्ति मंत्रालय (विदेशी व्यापार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3323 तारीख 14 अगस्त, 1969 में निम्नलिखित संशोधन किए जायेंगे, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना के नीचे वर्णित सारणी के स्तम्भ (2) में —

(1) "कोचीन क्षेत्र (इसमें केरल, मैसूर के राज्य और लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदिवि के संघ राज्य क्षेत्र आते हैं)" शीर्षक के नीचे मद 8 के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायगी, अर्थात :—

"8 उप मुख्य कार्यपालक, निर्यात निरीक्षण अधिकरण-कोचीन, मनोहर बिल्डिंग, एम० जी० रोड, एरनाकुलम, कोचीन-11 पदेन संयोजक"

(2) "मुम्बई क्षेत्र (इसमें महाराष्ट्र, गुजरात के राज्य और गोवा, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र आते हैं)" शीर्षक के नीचे मद 5, 6 और 7 के स्थान पर निम्नलिखित मदें प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात :—

"5. प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार सहकारी संघ लि० 3, महात्मा फूले फिश मार्केट मुम्बई ।

6. निदेशक हाफकिन इन्स्टीट्यूट, ओल्ड गवर्नमेंट हाउस, मुम्बई-12.

7. उप मुख्य कार्यपालक निर्यात निरीक्षणश्र भिकरण—मुम्बई 11/21, मेथ्यू रोड (दूसरी मंजिल) ,मुम्बई–4. पदेन संयोजक ।"

(3) "मद्रास क्षेत्र (इसमें आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्य और पांडेचेरी के संघ राज्य आते हैं)"

"6 उप निदेशक निर्यात निरीक्षण अभिकरण–मद्रास, 123, माउन्ट रोड, मद्रास–6. पदेन संयोजक ।"

[सं० 60(39) ई० आई० ई० पी०/67]

New Delhi, the 20th November 1970

S.O. 3831.—In pursuance of rule 6 of the Export of Fish and Fish Products (Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade and Supply (Department of Foreign Trade) No. S.O. 3322 dated the 14th August, 1969, read with the notification of the Government of India in the Ministry of Foreign Trade No. S.O. 2647 dated the 25th July 1970, namely:—

In column (2) of the Table appearing below the said notification, under the heading "Bombay Region (covering the States of Maharashtra, Gujarat and the Union Territories of Goa, Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli)":—

(i) Serial number 6 and the entries relating thereto shall be deleted.

(ii) Serial numbers 7 and 8 shall be re-numbered as Serial numbers 6 and 7 respectively.

[No. 60(2)/EIEP/67.]

M. K. B. BHATNAGAR,
Deputy Director (Export Promotion).

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1970

का०आ० 3831—मछली और मछली उत्पाद (निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 6 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के विदेशी व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2647 तारीख 25 जुलाई, 1970 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व विदेशी व्यापार और आपूर्ति मंत्रालय (विदेशी व्यापार विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 3322, तारीख 14 अगस्त, 1969, में एतद्द्वारा निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में, "मुम्बई प्रदेश (जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात के राज्य और गोवा, दमण, द्वीव, दादर और नागर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र हैं)" शीर्षक के नीचे :—

(i) क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियां काट दी जाएंगी ।

(ii) क्रम संख्या 7 और 8 क्रमशः संख्या 6 और 7 के रूप में पुनः संख्याकित की जाएंगी

[सं० 60(2) ई आई ई पी/67]

एम० के० बी० भटनागर,
उप निदेशक (निर्यात संवर्धन) ।

(CARDAMOM CONTROL)

New Delhi, the 9th November 1970

S.O. 3832.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 4 of the Cardamom Act, 1965 (42 of 1965), the Central Government hereby appoints Shri T. V. Swaminathan, Chairman, Rubber Board, Kottayam, as Chairman of the Cardamom Board, Ernakulam (Kerala), with effect from the afternoon of the 3rd October, 1970, in place of Shri E. C. Sanker, in addition to his own duties as Chairman of the Rubber Board.

[No. F. 29(69) Plant(B)/69.]

N. N. MALHAN, Dy. Director.

(इलायची नियंत्रण)

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1970.

का० आ० 3832—इलायची अधिनियम, 1965 (1965 का 42) की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री टी० वी० स्वामीनाथन, अध्यक्ष, रबड बोर्ड, कोट्टायम को, रबड बोर्ड के अध्यक्ष पद के अपने कार्य भार के अतिरिक्त, 3 अक्तूबर, 1970 के अपराह्न से, श्री इ० सी० शंकर के स्थान पर, इलायची बोर्ड, एर्नाकुलम (केरल) का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[सं० फा० 29 (69) प्लांट (ख)/69]

एन० एन० मल्हन, उप निदेशक।

(Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

Calcutta, the 12th June 1970

S.O. 3833.—Shri Sailesh Mazumdar, 39/5, Broad Street, Calcutta was granted an import licence No. P|A|1314459|C|XX|34|C|29-30, dated the 21st, January, 1970. He has applied for a duplicate Customs copy of the licence on the ground that the original customs copy of the licence has been lost or misplaced.

It has been declared that the original licence was not registered with any Custom House and not utilised at all.

In support of his contention, the applicant has filed an Affidavit sworn before the Presidency Magistrate, Calcutta.

I am satisfied that the Original licence No. P|A|1314459|C|XX|C|29-30, dated 21st January, 1970 (Customs copy) has been lost and direct that a duplicate licence (Customs copy) should be issued to the applicant. The Original licence is cancelled.

[No. 284(b)-IV/66/69-70/AV-I.]

B. B. MUKHERJEE,
Dy. Chief Controller of Imports & Exports
for Jt. Chief Controller of Imports & Exports

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय)

आदेश

कलकत्ता, 12 जून, 1970

एस० ओ०. 3833 :—श्री सैलेश मजूमदार, 39/5, ब्रोड स्ट्रीट, कलकत्ता को आयात लाइसेंस संख्या पी/ए/1314459/सी/एक्स एक्स/34/सी/29—30, दिनांक 21-1-70 स्वीकृत किया गया

था । उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए आवेदन किया है । इस के लिए उन्होंने यह आधार दिया है कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रति खो गई है । अथवा गलत स्थान पर रख दी गई है ।

यह बता दिया गया है कि मूल लाइसेंस किसी सीमा-शुल्क कार्यालय में पंजीकृत नहीं हुआ था और न उसका कोई प्रयोग ही किया गया था ।

इस तर्क के समर्थन में, आवेदक ने प्रैजीडेंसी मजिस्ट्रेट के सामने ली हुई कसम का एक शपथ-पत्र जमा किया है ।

मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि मूल लाइसेंस सं० पी/ए/1314459/सी/एक्स एक्स/34/सी/29-30, दिनांक 21-1-70 (सीमा-शुल्क प्रति) खो गया है और आदेश है कि अनुलिपि लाइसेंस (सीमा-शुल्क प्रति) आवेदक को जारी किया जाना चाहिए । मूल लाइसेंस रद्द किया जाता है ।

[सं० 284 (बी)-4/66/69-70/ए० पी० I.]

बी० बी० मुखर्जी,
उप-मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात,
वास्ते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 6th November 1970

S.O. 3834.—M/s. National Newsprint & Paper Mills Limited, Nepanagar, M.P., were granted import licence No. P/D/2169478, dated 19th May, 1969, against U.K. Non-Kipping of E.2 Million out of E.7 million Non-Project Loan, dated 19th June, 1967, for the import of paper making felts valued at Rs. 9,00,000. They have requested for the issue of duplicate exchange control copy of the licence on the ground that the original exchange control copy of the licence has been lost/misplaced by them. It has been further reported by the licensee that the licence had an unutilised balance of Rs. 154300. The licence was registered with Bombay Custom Office.

2. In support of their contention the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Exchange Control Purpose Copy of the licence No. P/D/2169478, dated 19th May, 1969, has been lost/misplaced and directs that a duplicate Exchange Control Purposes Copy of the said licence should be issued to them. The original Exchange Control Purposes copy is cancelled.

The duplicate Exchange Control copy is being issued separately.

[No. F. Paper/32(7)/68-69/R.M.II.]

G. D. BAHL,
Dy. Chief Controller of Imports & Exports.
for Chief Controller of Imports & Exports.

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1970

एस० ओ० 3834.—सर्वश्री नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि०, नेपा नगर, मध्य प्रदेश को ई० 7 मिलियन नान-प्रोजेक्ट लोन दिनांक 16-6-67 में से ई० 2 मिलियन के यू० के० नोन-

किण्विंग के लिए कागज से बनाए जाने वाले नमदों के आयात के लिए 9,00,000/–रुपये के मूल्य का आयात लाइसेंस संख्या पी/डी/2169478, दिनांक 19–5–1969 जारी किया गया था। उन्होंने लाइसेंस की मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मल-मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति उनसे खो गई है/अस्थानस्थ हो गई है। लाइसेंसधारी द्वारा आगे यह सूचना दी गई है कि लाइसेंस का 154300/–रुपये का उपयोग करना बाकी था। लाइसेंस सीमा-शुल्क कार्यालय, बम्बई से पंजीकृत किया गया था।

2. अपने तर्क की पुष्टि में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है, अधोहस्ताक्षरी सतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या पी/डी/2169478, दिनांक 19–5–69 की मूल मुद्रा–विनिमय नियंत्रण सम्बन्धी प्रति खोई गई है/अस्थानस्थ हो गई है और आदेश देता है कि उनको उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण सम्बन्धी प्रति की अनुलिपि जारी की जानी चाहिए। मूल मुद्रा-विनिमय नियंत्रण सम्बन्धी प्रति को रद्द किया जाता है।

मद्रा–विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि अगल से जारी की जा रही है।

[सं० पेपर/32(7)/68–69/आर एम–III]

जे० पी० बहल,

उप मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात,

कृते मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात।

(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports)
(Central Licensing Area)

CANCELLATION ORDER

New Delhi, the 21st September 1970

S.O. 3835.—M/s. Raj Traders, 10041/2 Multani Dhanda Paharganj, New Delhi were granted import licence No. P/K/2603977 dated 5th March, 1970. They have applied for duplicate copy (Custom purposes copy only) of licence on the ground that the original custom purposes copy have been lost. It is further stated that the original licence was not registered and not utilized at all.

In support of this contention, the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the original custom purposes copy of licence No. P/K/2603977 dated 5th March, 1970 has been lost and direct that the duplicate licence (Custom copy) should be issued to the applicant. The original custom purposes copy of licence is cancelled.

[No. Gem. 74/OD.69/SC.IV/CLA.]

D. S. MORMRIMA,
Dy. Chief Controller of Import and Export.

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

(केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र)

आदेश

नई दिल्ली, 21 सितम्बर 1970

एस० ओ० 3835.—सर्वश्री राज ट्रेडस, 10041/2, मुल्तानी धांडा, पहाड़गंज, नई दिल्ली को आयात लाइसेंस संख्या पी/के/2603977, दिनांक 5–3–70 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति (सीमा शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति मात्र) के लिए आवेदन किया

इसके लिए यह आधार दिया है कि मूल सीमा-शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति खो गई है। उनके द्वारा आगे यह बताया गया है कि मूल लाइसेंस पंजीकृत नहीं किया गया था और उसका बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया था।

इस तर्क के समर्थन में, आवेदन ने एक शपथ पत्र जमा किया है। मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि लाइसेंस संख्या पी/के/2603977, दिनांक 5-3-70 की मूल सीमा-शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति खो गई है और निदेश देता हूं कि अनुलिपि लाइसेंस (सीमा शुल्क प्रति) आवेदक को जारी की जानी चाहिए। मूल सीमा शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति रद्द की जाती है।

[सं० जी० ई० एम० 74/ओ० डी० 69/एस० सी० 4/सी० एल० ए०]

डी० एस० मोरक्रीमा,

उप-मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

(Department of Health)

New Delhi, the 10th November 1970

S.O. 3836.—In exercise of the powers conferred by Rule 8 of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, the Central Government hereby authorises Dr. B. N. Chowdhuri, Deputy Director, Central Drugs Laboratory, Calcutta, to sign certificates under the said Rules issued by the Central Drugs Laboratory, Calcutta, with effect from 10th October, 1970, during the absence abroad of Dr. D. Ghosh, Director, Central Drugs Laboratory, Calcutta.

[No. F. 3-1/70-D.]

S. SRINIVASAN, Under Secy.

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1970

एस० ओ० 3836.—औषध एवं अंगराग नियमावली, 1945 के नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतत् द्वारा केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला कलकत्ता के निदेशक डा० डी० घोष के विदेश चले जाने पर उनकी अनुपस्थिति में केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता द्वारा उक्त नियमावली के अधीन 10 अक्तूबर, 1970 से जारी किये गये प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता के उप निदेशक डा० बी० एन० चौधरी को प्राधिकृत करती है।

[सं० फा० 3-1/70-डी०]

एस० श्रीनिवासन, अवर सचिव।

(Department of Health)

ORDER

New Delhi, the 17th November 1970

S.O. 3837.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 17-43/59-MI, dated the 9th January, 1961, the Central

Government has directed that the Medical qualification, M.D. (University of Illinois, USA) shall be recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. Visscher Lois Helena who possesses the said qualification is for the time being attached to the Christian Hospital, Kasganj, Uttar Pradesh for the purposes of teaching and charitable work;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies;

(i) a further period of two years ending with the 1st July, 1972, or

(ii) the period during which Dr. Visscher Lois Helena is attached to the said Christian Hospital, Kasganj, Uttar Pradesh whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. F.19-27/70-MPT.]

M. C. MISRA, Dy. Secy.

(स्वास्थ्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1970

का० आ० 3837.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 9 जनवरी 1961 की अधिसूचना सं० 17—43/59—एम०पी०टी० द्वारा केन्द्रीय सरकार ने आदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम., 1956(1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए इल्लिनौइस विश्वविद्यालय, अमरीका द्वारा अनूदत्त "एम० डी०" नामक चिकित्सा अर्हता मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।

और यतः डा० विसचर लौइसहेले ना को जिनके पास की उक्त अर्हता है फिलहाल कासगंज उत्तर प्रदेश स्थित क्रिश्चियन अस्पताल के साथ अध्यापन और धर्मार्थ —कार्य के प्रयोजनों के लिए लगाया गया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप धारा (1) के परन्तुक के खण्ड (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा

(i) पहली जुलाई 1972 को समाप्त होने वाली दो वर्ष की एक और अवधि को, अथवा

(ii) डा० विसचर लौइसहेले ना के कासगंज, उत्तर प्रदेश स्थित क्रिश्चियन अस्पताल से संबद्ध रहने की अवधि को जो भी कम हो, वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है जिसमें कि पूर्वोक्त डाक्टर की मेडिकल प्रैक्टिस सीमित होगी।

[सं० फा० 19—27/70—एम० पी० टी०]

महेश चन्द्र मिश्र, उप सचिव।

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 26th October 1970

S.O. 3838.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the Hindustan Shipyard Limited; Visakhapatnam from the provisions of the said Act except Chapter V-A thereof for a period of 6 months with effect from the 1st April, 1970 upto and inclusive of the 30th September, 1970.

[No. 6(30)/69-HI.]

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1970

का० आ०—3838 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948(1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापटनम को उक्त अधिनियम, के उपबंधों से उसके अध्याय 5–क के सिवाए, प्रथम अप्रैल, 1970 से 30 सितम्बर, 1970 तक जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, 6 मास, की कालावधि के लिए छूट देती है ।

[संख्या फाइल 6(30)/69–एच० आई०]

New Delhi, the 20th November 1970

S.O. 3839.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri R. N. Dave to be an Inspector for the area of Daman in the Union Territory of Goa, Daman and Diu for the purposes of the said Act and of any Scheme framed thereunder, in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government, and in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oil field or a controlled industry.

[No.A.12015(1)/70-PF.1(i).]

नई दिल्ली 20 नवम्बर, 1970

का० आ० 3839—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री आर० एन० दवे को उक्त अधिनियम और उसके अधीन विरचित किसी स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के सम्बन्ध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन सम्बन्ध में गोवा, दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्र में दमण क्षेत्र के लिए निरीक्षक नियुक्ति करती है ।

[स० ए० /20/5(1)/70–पी० एफ० 1(i)

S.O. 3840.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 16 of Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby exempts all handloom factories organised as industrial co-operatives, as a class, from the operation of the said Act for a further period of five years from the 1st January, 1970 upto and inclusive of the 31st December, 1974.

[No. 11(3)/70-PF-II.]

DALJIT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1970

का० आ०–3840 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 16 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा औद्योगिक सहकारिता के रूप में संगठित सभी हाथकरघा कारखानों को एक वर्ग के रूप में उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से प्रथम जनवरी, 1970 से 31 दिसम्बर, 1974 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, और आगे पांच वर्ष की कालावधि के लिए छूट देती है ।

[संख्या 11(3)/70–पी० एफ०–2]

द जीत सिंह, अपर सचिव

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 11th November 1970

S.O. 3841.—Whereas the Central Government, being satisfied that the public interest so required, had declared by a notification made in pursuance of the provisions of the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), [being the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment No. S.O. 1847, dated the 5th May, 1970)] service in any oil-field, to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the said 22nd May, 1970;

And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said service to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 22nd November, 1970.

[No. F. 1/77/70-LR.I.]

(श्रम और रोजगार विभाग)]

नई दिल्ली, नवम्बर 1970

का० आ० 3841—यतः केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ठ) के उपखण्ड (VI) के परन्तुक के उपबंधों के अनुसरण में एक अधिसूचना [भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना स० का० आ० 1847 तारीख 5 मई, 1970] द्वारा किसी तेल-क्षेत्र में सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 22 मई, 1970 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ठ) के उपखण्ड (VI) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 22 नवम्बर, 1970 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं० 1/77/70-एल आर I]

एस० एस० सहस्रनामन, अपर सचिव ।

New Delhi, the 21st November 1970

S.O. 3842.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the Hindustan General Insurance Society Limited, Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th November, 1970.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

REFERENCE No. 40 OF 1970

PARTIES:

Employers in relation to the Hindustan General Insurance Society Limited Calcutta,

AND

Their workmen

PRESENT:

Mr. B. N. Banerjee, Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers—Sri A. K. Dutt, Advocate, along with Sri S. B. Kar Advocate.

On behalf of Workmen—Sri D. L. Sen Gupta, Advocate.

STATE: West Bengal. INDUSTRY: Insurance.

AWARD

By Order No. 40/21/70-LR.I, dated August 17, 1970, the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred the following dispute between the employers in relation to the Hindustan General Insurance Society Limited, Calcutta, and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:

"Whether the action of the management of the Hindustan General Insurance Society Limited, Calcutta, in terminating the services of Sarvashri Rajit Naik and Raghu Jamadar, wiht effect from the 7th January 1970, is justified? If not, to what relief are they entitled and from which date?"

2. The case pleaded by the workmen, represented by the Commercial Establishment Sub-staff Union, is hereinafter briefly related. The two concerned workmen were members of the Sub-staff of the employer company and were designated as Jamadars. They used to work as Sweepers, at the residence of Sri P. N. Talukdar, at one time the Managing Director of the employer company. Workman Ranjit Naik put in about two and half years of service and workman Raghunath Jamadar put in about 16 years of service. Both Ranjit and Raghunath were retrenched, by letters respectively dated January 5, 1970 and January 7, 1970, without any compensation, in violation of the principles of Section 25F of the Industrial Disputes Act and particularly without following the principle of 'last come first go' in the matter of retrenchment. They pleaded that there was no surplusage in the company and that their retrenchment was influenced by extraneous consideration and as such illegal, unjustified and *mala fide*.

3. The management also filed a written statement. In paragraph 1 of the written statement they raised certain preliminary objections as to the competency of the reference. Of the preliminary objections raised, those quoted in paragraphs 1(c) and 1(d) only insisted upon at the time of hearing. I have dealt with the preliminary objections, in my order dated November 6, 1970, and have over-ruled both of them. My order on the preliminary objections is attached to this Award as an Appendix.

4. In paragraph 5 of the written statement, the employer Company pleaded:

"The Company specifically denies that Sri Ranjit Naik and Shri Raghu Jamadar were the members of the Sub-staff of the Company. The Company states that the said two persons all along worked as domestic servants at 5, Sunny Park, Calcutta-19 and the expenses in respect of the two persons were reimbursed by the Company as a part of the benefits enjoyed by Shri P. N. Talukdar, the then Managing Director of the Company. The Company states in this connection that the services rendered by those two persons were exclusively private and personal in nature and were confined in the private residence of Shri Talukdar, who was both Managing Director and Chairman of the Company. The Company further states that Shri Talukdar resigned the post of Managing Director and remained only the Chairman of the Board of Directors of the Company and was free from all executive functions and as such was not entitled to be re-imbursed by the company the expenses incurred in respect of the services rendered by the domestic servant in his residence as a result whereof the services of those two persons were dispensed with."

5. In paragraph 7 of the written statement, the company stated that the question of notice under the Industrial Disputes Act and the question of following the principle of 'last come first go' were absolutely pointless and irrelevant because the two workmen worked at the residence of Shri P. N. Talukdar.

6. In paragraph 8 of the written statement it was also pleaded that the two concerned workmen never worked under the Company and the question of surplusage is pointless and irrelevant.

In the background of these pleadings, I have to decide this reference.

7. I may note, at this stage, that I was deprived of the services of the learned Advocates for the management, because they elected to retire from the case after

the preliminary objections were decided against the management. Nevertheless, I am in this fortunate position, amongst the multiple forms of obstructionism that I had to face in this case, that the management had cared to file their documents and also examine their witness.

8. On behalf of the management Dinesh Chandra Bardhan, an officer in the Accounts Department, was examined. In his examination-in-chief he stated:

> "By subordinate staff I mean Jamadars, Sweepers, bearers and the like. The salaries are paid to the subordinate staff after entry in their respective salary cards. (Shown the bundle of pay cards for the years 1966 and 1967, collectively marked Ex. D)."

It appears from Exts. A and B, marked by consent, that the salaries of Raghu Jamadar and Ranjit Naik were paid after entry in the salary cards, in the same way as salaries of other sub-staffs used to be paid. It is not stated by anybody that the salaries payable to the two concerned workmen were drawn by Sri P. N. Talukdar by way of perquisites and then paid by him to the concerned workmen. On the other hand, Dhirendra Chandra Bardhan plainly stated in his cross-examination:

> "I cannot say whether the salary of Raghu Jamadar is included in the gross salary of P. N. Talukdar.'

It is also significant that the two letters of termination of service (Exts. 2 and 3) were signed and caused to be served upon the two workmen not by Sri P. N. Talukdar but by the Manager of the Hindustan General Insurance Society Limited. The two letters are in identical language and I set out herein below one of them by way of illustration:

> "We are to inform you that your *services with the Society* will not be necessary on and from 7th January, 1970 and is hereby terminated from the said date.
>
> You can collect your dues as per Society's rules from the Cash Department any day during office hours." (Underlined by me for emphasis).

It is noteworthy that in the above letter there is a clear admission that the services of the workmen were with the Society and not with Sri P. N. Talukdar and that the workmen were asked to collect their dues from the Cash Department of the management's office and not from Sri P. N. Talukdar. The letters of appointment were not produced before me. It is, however, nobody's case that letters of appointment were in fact issued to these two workmen or such letters were issued by Sri P. N. Talukdar. I am, on the materials, unable to hold that the two workmen were private domestic servants of Sri P. N. Talukdar. They were employees under Hindustan General Insurance Society Ltd., which was engaged in the insurance industry.

9. I need emphasise upon two things before I proceed further. It is not the case of the management that the services of the workmen were terminated under any provisions of the Standing Orders of the Company, nor it is the case of the management that their termination of service was based upon their conditions of service nor because of efflux of time for which they had been appointed. According to the management, their services were terminated because they were no longer wanted on account of the retirement of Sri P. N. Talukdar from the position of Managing Director. The case pleaded by the workmen was that they were wrongfully retrenched.

10. I shall first deal with the case of retrenchment. Mr. D. L. Sen Gupta, learned advocate for the workmen, invited my attention to an observation by the Supreme Court in the case of *Barsi Light Railway Company Ltd.* vs. *Joglekar (K.N.) and others* (1957) I LLJ, 243(252) to the following effect:

> "....we hold, contrary to the view expressed by the Bombay High Court, that retrenchment as defined in S. 2(oo) and as used in S. 25F has no wider meaning than the ordinary, accepted connotation of the word: it means the discharge of surplus labour or staff by the employer for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action, and it has no application where the services of all workmen have been terminated by the employer on a real and *bona fide* closure of business as in the case of Sri Dinesh Mills, Ltd. or where the services of all workmen have been terminated by the employer on the business or undertaking being taken over by another employer in circumstances like those of the railway company.'

He submitted that since, according to the management, the services of the workmen were terminated because their services were no longer required, that itself

was tantamount to saying that the workmen were discharged as surplus labour. I am not satisfied with this argument of Mr. Sen Gupta. On the materials before me, there is no doubt that the workmen were serving under the Hindustan General Insurance Society Limited. They were deputed to work at the house of Sri P. N. Talukdar. Because of retirement of Sri P. N. Talukdar from the position of Managing Director, they did not necessarily become surplus workmen. They might be deputed to work at the place of the new Managing Director or to work at the office or to work at any of the offices of the management Company. Without more, I cannot proceed on the assumption that because the services of the two workmen were not any more required at their one time place of work, they became certainly surplus workmen. At any rate, the management did not retrench them, if fact, even if they could do so.

11. I now turn to the case of the management that the services of the workmen were terminated, not under the Standing Orders, not under the Service conditions, not for blameworthiness, not for efflux of time, but merely because their services were no longer required. This, in my opinion, is high-handed attitude for the management to take up. In a modern welfare society, the old 'hire and fire' attitude in industrial employment has undergone considerable change. It is no longer open to the management to hire workmen in an industrial concern and to get rid of them in the manner as done in this case. The workmen could have surely been discharged under the Standing Orders if any applied. They might have been discharged under their service conditions if there was such a condition for discharge. Their services might have come to an end, if their period of appointment had expired. They might have been dismissed for blameworthiness in accordance with the prescribed procedure. But they could not be thrown out at the sweet will of the management without compensation or without more.

12. In the view that I take, I hold that the action of the management of Hindustan General Insurance Society Limited, Calcutta, in terminating the services of Sarvashri Ranjit Naik and Raghu Jamadar, with effect from the 7th January, 1970, was not justified. The workmen are entitled to be reinstated in their services with full back wages from the date of their wrongful termination of service, less sums if any, already paid.

This is my award.

(Sd.) B. N. BANERJEE,
Presiding Officer.

Dated. November 7, 1970.

APPENDIX

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

REFERENCE No. 40 OF 1970

PARTIES:

Employers in relation to the Hindustan General Insurance Society Limited, Calcutta,

AND

Their workmen

PRESENT:

Mr. B. N. Banerjee, Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers—Sri A. N. Dutt, Advocate with Sri B. S. Kar, Advocate.

On behalf of Workmen—Sri D. L. Sen Gupta, Advocate.

ORDER

By Order No. 40/21/70-LRI.I, dated August 17, 1970, the Central Government referred the following dispute between the employers in relation to the Hindustan General Insurance Society Limited, Calcutta and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:

"Whether the action of the management of the Hindustan General Insurance Society Limited, Calcutta, in terminating the services of Sarvashri Ranjit Naik and Raghu Jamadar, with effect from the 7th January, 1070 is justified? If not, to what relief are they entitled and from which date?"

2. The case pleaded by the workmen, represented by the Commercial Establishment Sub-staff Union, is hereinafter briefly related. The two concerned workmen were members of the Sub-staff of the employer company and were designated as Jamadars. They used to work as Sweepers at the residence of Sri P. N. Talukdar, the then Managing Director of the employer company. The workman Ranjit Naik put in about two and half years of service and the workman Raghunath Jamadar put in about 16 years of service. Both Ranjit and Raghunath were retrenched, by letters dated January 5, 1970 and January 7, 1970, without any compensation, in violation of the principles of Sec. 25F of the Industrial Disputes Act and particularly without following the principle of 'last come first go' in the matter of retrenchment. They pleaded that there was no surplusage in the company and that their retrenchment was influenced by extraneous consideration and as such illegal, unjustified and *mala fide*.

3. I need not, at this stage, concern myself with the written statement of the employer company, in so far as it deals with the merits of the case. Mr. A. K. Dutt, learned Advocate for the employer Company, urged two preliminary objections as to the maintainability of the reference and insisted upon a decision on the preliminary objections first of all, inasmuch as, in his submission, those two preliminary objections touched upon the jurisdiction of the tribunal to decide the reference on merits. The two preliminary objections, which were insisted upon by him, are pleaded in paragraph 1 of the written statement and are set out below:

(i) that the Commercial Establishment Sub-staff Union is not competent to raise the aforesaid dispute either in the representative capacity and/or otherwise.

(ii) that the work in which the two persons were engaged was not an industry as defined in Industrial Disputes Act.

In elaboration of the second branch of the preliminary objection, it was further pleaded in paragraph 5 of the written statement:

"The Company specifically denies that Sri Ranjit Naik and Shri Raghu Jamadar were the members of the Sub-Staff of the Company. The Company states that the said two persons all along worked as domestic servants at 5, Sunny Park, Calcutta-19 and the expenses in respect of the two persons were reimbursed by the Company as a part of the benefits enjoyed by Shri P. N. Talukdar, the then Managing Director of the Company. The Company states in this connection that the services rendered by those two persons were exclusively private and personal in nature and were confined to the private residence of Shri Talukdar, who was both Managing Director and Chairman of the Company. The Company further states that Shri Talukdar resigned the post of Managing Director and remained only the Chairman of the Board of Directors of the Company and was free from all executive functions and as such was not entitled to be re-imbursed by the company the expenses incurred in respect of the services rendered by the domestic servant in his residence as a result whereof the services of those two persons were dispensed with."

4. Although I am not satisfied that the objections taken by Mr. Dutt are of such a nature as touch upon the jurisdiction of this Tribunal, without more, and can be decided as pure questions of law, yet then I have chosen to give my decisions on the preliminary objections, out of deference to the insistence put up by Mr. Dutt.

5. Turning now to the first branch of the preliminary objection, I have to see whether the Commercial Establishment Sub-Staff Union is a trade union of the employees of Hindustan General Insurance Society Limited or is a stranger trade union. On this point, the management examined Dinesh Chandra Bardhan, an officer in the Accounts department of the company. In his evidence he stated:

"There is only one trade union in the office of the Hindustan General Insurance Society Limited. That is a unit of All India General Insurance Association.

To Tribunal

I know that there is no other trade union in the office.

Examination-in-chief contd.

Formerly I was myself a member of that unit of trade union. At that time, some of the members of the subordinate staff were members of that trade union."

In cross-examination he said, 'there is no separate union in the name of Hindustan General Insurance Society Limited'.

5. The two concerned workmen also gave evidence. Workman Raghunath (*alias* Raghu Jamadar) stated in his evidence:

> "I know there is a trade union in the office. I am a member of Commercial Establishment Sub-staff union. I became a member of that union after my services were terminated. I do not know if any other Jamadar/Sweeper is a member of Commercial Establishment Sub-staff Union."

The other workman, Ranjit Naik, stated in course of his cross-examination:

> "I know there are Jamadars and sweepers working in the office of the employer company. I do not know whether those Jamadars/Sweepers have a separate union. When I received the letter of termination of service, I approached Satin Babu of Commercial Establishment Sub-staff Union. I came to know of that union because I heard of the union from others and also saw the trade union to conduct a procession..I do not know whether any of the office Jamadar/Sweeper is a member of the Sub-staff union."

On this sort of evidence, it is difficult for me to hold that the Commercial Establishment Sub-staff Union is a domestic Trade union of Hindustan General Insurance Society Limited. The witness examined on behalf of the management categorically disowns any trade union, excepting a unit of All India General Insurance Association, operating in Hindustan General Insurance Society Limited. The workmen gave colourless evidence and do not claim that the Commercial Establishment Sub-staff union is a domestic union of the workmen of Hindustan General Insurance Society Limited.

6. Even though I express the tentative opinion that the Commercial Establishment Sub-Staff Union is not a domestic trade union of the workmen of Hindustan General Insurance Society, on which basis I merely proceed for want of better evidence, yet then the reference does not become incompetent because the two workmen were being represented by a stranger trade union. Section 36(1) of the Industrial Disputes Act is couched in the following language:

> "36(1) A workman who is a party to a dispute shall be entitled to be represented in any proceeding under this Act by—
>
> (a) an officer of a registered trade union of which he is a member;
>
> (b) an officer of a federation of trade unions to which the trade union referred to in clause (a) is affiliated;
>
> (c) where the worker is not a member of any trade union, by an officer of any trade union connected with, or by any other workman employed in, the industry in which the worker is employed and authorised in such manner as may be prescribed."

Now, even if the Commercial Establishment Sub-Staff union was a stranger trade union and even if the membership taken by one of the workmen, namely Raghu Jamadar, after the termination of his service was of little consequence even then Section 36(1) (c) entitles the Commercial Establishment Sub-staff Union to represent the two workmen. This is all the more so because it is nobody's case that there is no trade union of the name of Commercial Establishment Sub-staff Union or that the said trade union has no connection with the Insurance industry. In this context, I need remind myself of the following observations by Gajendragadkar, J (as he then was) in the case of *Newspaper Limited, Allahabad* vs *State Industrial Tribunal* (1960) II LLJ 37:

> "Both the courts have held, and rightly, that it is not necessary that a registered body should sponsor a workman's case to make it an industrial dispute. Once it is shown that a body of workmen either acting through their union or otherwise have sponsored a workman's case it becomes an industrial dispute."

7. Mr. A. K. Dutt next emphasised upon the point that the cause of the two workmen were not espoused by any body of workmen or by a trade union. He, therefore, argued that it was at best an individual dispute and should not be treated as an industrial dispute. In the case of *Ramprasad Viswakarma* (1961) I LLJ 504 Das Gupta, J. no doubt observed that it was well settled that a dispute between an individual workman and an employer could not be an industrial dispute as defined in Section 2(k) of Industrial Disputes Act, unless taken up by a union of workmen or by a considerable number of workmen. His Lordship referred to an earlier decision of the Supreme Court, per Venkatarama Ayyar, J, in *Central Provinces*

Transport Services Limited vs *Raghunathgopal Patwardhan*, (1951) I LLJ 27 and observed:

> "This view which has been reaffirmed by the Court in several later decisions recognise the great importance in modern industrial life of collective bargaining between the workmen and the employers. It is well known how before the days of collective bargaining labour was at a great disadvantage in obtaining reasonable terms for contracts of service from his employer. As trade unions developed in the country and collective bargaining became the rule, the employers found it necessary and convenient to deal with the represnetatives of workmen, instead of individual workmen, not only for the making or modification of contracts but in the matter of taking disciplinary action against one or more workmen and as regards all other disputes.
>
> The necessary corollary to this is that the individual workman is at no stage a party to the industrial dispute independent of the union. The union or those workmen, who have by their sponsoring turned the individual dispute into an industrial dispute, can therefore claim to have a say in the conduct of the proceedings before tribunal".

In reply to the argument advanced by Mr. Dutt, Mr. D. L. Sen Gupta, learned Advocate for the workmen, invited my attention to Section 2A of the Industrial Disputes Act (introduced by the amending Act of 1965) reading:

> "2A. Where any employer discharges, dismisses, retrenches or otherwise terminates the services of an individual workman, any dispute or difference between that workman and his employer connected with, or arising out of such discharge, dismissal retrenchment or termination shall be deemed to be an industrial dispute notwithstanding that no other workman nor any union of workmen is a party to the dispute,"

and submitted that after the insertion of Section 2A in the Industrial Disputes Act, to the extent of individual dispute with respect to "discharge, dismissal, retrenchment or otherwise termination of service" of a workman, the position of law has considerably changed. Because of the Changed law, Ram Prasad Viswakarma's case (supra) does not hold the field now where the dispute relates to discharge, dismissal, retrenchment or termination of service of a workman. To this argument Mr. A. K. Dutt had an off hand rejoinder. He submitted that the language of the order of Reference was such as would be appropriate in the case of a dispute between the management and the main body of workmen or the total number of workmen. In my opinion, there is substance in the contention of Mr. D. L. Sen Gupta. The opening words of the order of reference reads:

> "Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute existed between the employers in relation to the Hindustan General Insurance Society Limited, Calcutta and their workmen in respect of the matters specified in the schedule hereto annexed."

The concerned workmen were two in number. Therefore, the language used in the order of reference was not totally in-applicable in a case of individual dispute between two workmen and the management. It is true that far better language would have been

> "....a dispute exists between the employer in relation to the Hindustan General Insurance Society Limited, Calcutta and two of their workmen in respect of the matters specified in the schedule hereto annexed."

Nevertheless, the language as it stands is not wholly in-applicable in the case of the industrial dispute raised by only two workmen.

8. Moreover, it appears from Ex. 5 and Ex. 6, that the workmen individually made demands to the management for their re-instatement after their alleged wrongful dismissal. Thereafter, it appears from Ext. 8, that the President of the Commercial Establishment Sub-staff union was advised and authorised by Ranjit Naik to take up the case. It also appears from the Failure report of the Conciliation Officer, marked Ex. 11 and 11(a), that the dispute reached him as an industrial dispute between the management and the two of their workmen.

9. Mr. Dutt no doubt invited my attention to the opening of words of the 3rd paragraph in Ex. 11(a), in which the Conciliation Officer used the expression "Union's case". But this is, in my opinion, an inappropriate expression in the context in which he was conciliating.

10. Mr. Dutt lastly argued, in this branch of preliminary objection, that the dispute had not been taken up before the management but was straightway taken before the Conciliation Officer. If that had been in fact so, the reference would have been bad under the authority of the decision of the Supreme Court in *Sindhu Resettlement Corporation* vs. *Industrial Tribunal Gujarat*, 1968 I LLJ, 834. But in the instant reference, I have already observed that the dispute was taken up before the management by Exts. 5 and 6 but ineffectively. I, therefore, find no substance in the first branch of the preliminary objection.

11. Turning now to the second branch of preliminary objection, I have to remind myself of the definition of 'industry' as in Section 2(j) of the Industrial Disputes Act, which reads:

> "(j) 'industry' means any business, trade, undertaking, manufacture or calling of employers and includes any calling, service, employment, handicraft, or industrial occupation or avocation of workmen;"

The first part of the definition of the term 'industry' relates to employers while the second part in the workmen. The word 'industry' must take its colour from the definition itself and workman is to be regarded as one employed in an industry if he follows one of the vocations mentioned in the second part of the definition in conjunction with his employer engaged with the vocation mentioned in the first part of the definition. The terms 'business' and 'trade' are of wide amplitude and have definite economic content to the exclusion of professions but are concerned with the production, distribution and consumption of wealth and the production and availability of material services. Reference in this context may be made in the observation of the Supreme Court in the *Management of Safdarjang Hospital* vs *Kuldip Singh Sethi*, (1970) II LLJ 266. In the instant case, the employer company was no doubt engaged in an industry within the meaning of the definition hereinbefore quoted. The Managing Director of the Company was entitled to the services of two sweepers, who so far as it appears upto now, were employees under the Hindustan General Insurance Society Limited because their services were terminated by the Company and also they were paid out of the funds of the Company. That being so, they were workmen employed in an industry and were entitled to raise an industrial dispute over their wrongful termination of service within the meaning of Section 2A of the Industrial Disputes Act.

12. I, therefore, find nothing of substance in the second branch of the preliminary objection as well.

13. Both the objections failing, I shall now take up the case for hearing on merits.

Dated, November 6, 1970.

(Sd.) B. N. BANERJEE,
Presiding Officer.

[No. F. 40/21/70-LR.I.]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 18th November 1970

S.O. 3843.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri K. K. Ray as the member and Chairman of the Calcutta Dock Labour Board with effect from the 16th of November, 1970 *vice* Shri N. C. Sen Gupta who has been transferred and make the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1322 dated the 7th April 1967, namely:—

In the said notification, under the heading *"Members representing the Central Government"* in item (1) and in para 2 for the words and letter "Shri N. C. Sen Gupta" the following words and letters shall be substituted namely:—

"Shri K. K. Ray"

[No. 63/13/67-Fac.II/P&D.]

C. RAMDAS, Dy. Secy.

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 18 नवम्बर 1970

का० आ० 3843.—डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5क की उपधारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री के० के० रे को श्री एन० सी० सेन गुप्त के स्थान पर, जिनका स्थानांतरण हो गया है, 16 नवम्बर, 1970 से कलकत्ता डाक श्रम बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 1322, तारीख 7 अप्रैल, 1967 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि सदस्य" शीर्षक के अन्तर्गत मद (1) और पैरा 2 में "श्री एन० सी० सेन गुप्त शब्दों और वर्णों के लिए निम्नलिखित शब्द और वर्ण प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

"श्री के० के० रे"

[सं० 63/15/67-फैक०-21 पी० एण्ड डी०]

सी. रामधाम, उपसचिव।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 18th November 1970

S.O. 3844.—P.W.A./Mines/Rules/Am.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 26, read with section 24 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Payment of Wages (Mines) Rules, 1956, the same having been previously published as required by sub-section (5) of the said section 26, namely:—

1. These rules may be called the Payment of Wages (Mines) Amendment Rules, 1970.

2. In rule 2 of the Payment of Wages (Mines) Rules, 1956, (hereinafter referred to as the said rules) (i) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:—

'(g) "employer" means the owner of the mine and includes a contractor, an agent or manager or ~~any~~ other person responsible under section 3 of the Act for payment of wages and includes in the case of a deceased employer, his legal representative."

(ii) for clause (k), the following clause shall be substituted, namely:

(k) "person employed" or "employed person" means a person employed in a mine or an oil-field to whom the Act applies and includes, in the case of a deceased employed person, his legal representative."

3. For rule 6 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"6. *Preservation and maintenance of registers*:—

(1) Every register maintained under the Act or these rules shall be preserved for a period of three years after the date of the last entry made therein.

(2) The registers maintained under the Act or these rules shall be maintained in English and in Hindi or in the language understood by the majority of the persons employed in the mine: provided that where a register is maintained in Hindi or any other language a true translation thereof in English shall also be maintained.

4. After rule 6 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"6-A. *Production of registers and other records*:—

All registers and records required to be maintained by the employer under these rules shall on demand be produced before the Inspector:

Provided that where an establishment has been closed, the Inspector may demand the production of the registers and records in his office or such other public place as may be nearer to the employer."

5. For rule 22 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"2. *Penalties*: Whoever, being required under these rules, to maintain any register or records or to furnish any information or return fails to maintain such register or record or to furnish such information or return or fails to observe provisions of any of these rules shall, for each such offence, be punishable shall, for each such offence, be punishable with fine which may extend to five hundred rupees:

Provided that an employer who maintains the required register or record or furnishes the required return without making uptodate entries therein, or fails to display notices shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees."

6. In Form A, after Column 5 the following column shall be inserted, namely:—

"6. Number of persons affected."

[No. 19/13/68-Fac-1/LR-IV.]

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 18 नवम्बर 1970

का० आ० 3844.—पी० डब्ल्यू० ए०/माइंस/रूल्स/अमै० मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 24 के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1956 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम, जिन्हें उक्त धारा 26 की उपधारा (5) द्वारा यथा अपेक्षित पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1. ये नियम मजदूरी संदाय (खान) संशोधन नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

2. मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में,

(i) खण्ड (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(ढ) "नियोजक" से खान का स्वामी अभिप्रेत है और इसमें संविदाकर, अभिकर्ता या प्रबन्धक या अधि नियम की धारा 3 के अधीन मजदूरी के संदाय के लिए उत्तरदायी कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है और मृत नियोजक की दशा में इसमें उसका विधिक प्रतिनिधि सम्मिलित है।"

(ii) खण्ड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(ट) "नियोजित व्यक्ति" से खान या तेल-क्षेत्र में नियोजित वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको यह अधिनियम लागू होता है और मृत नियोजित व्यक्ति की दशा में इसमें उसका विधिक प्रतिनिधि सम्मिलित है।'

3. उक्त नियमों के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6. **रजिस्टरों का परिरक्षण और बनाए रखना**:—

(1) अधिनियम या इन नियमों के अधीन बनाए रखे गए प्रत्येक रजिस्टर को उसमें की गई अंतिम प्रविष्टि की तारीख के पश्चात् तीन वर्ष की कालावधि के लिए परिरक्षित रखा जाएगा।

(2) अधिनियम या इन नियमों के अधीन रखे गए रजिस्टरों को अंग्रेजी में और हिन्दी में या खान में नियोजित व्यक्तियों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली भाषा में रखा जाएगा;

परन्तु जहां रजिस्टर हिन्दी या किसी अन्य भाषा में रखा जाए वहां उसका अंग्रेजी में एक सही अनुवाद भी रखा जाएगा।

4. उक्त नियमों के नियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"6-क. **रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों को पेश करना** :—

उन सभी रजिस्टरों और अभिलेखों को, जिनका नियोजक द्वारा इन नियमों के अधीन रखा जाना अपेक्षित है, मांगे जाने पर निरीक्षक के समक्ष पेश किया जाएगा ;

परन्तु जहां किसी स्थापन को बन्द कर दिया गया है, निरीक्षक रजिस्टरों और अभिलेखों को अपने कार्यालय या ऐसे सार्वजनिक स्थान में, जो नियोजक के निकटतर हो, पेश करने की मांग कर सकता है"

5. उक्त नियमों के नियम 22 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"22. **शास्तियां** : जो कोई, जिससे इन नियमों के अधीन कोई रजिस्टर या अभिलेख रखने या कोई सूचना या विवरणी देने की अपेक्षा है, ऐसे रजिस्टर या अभिलेख के रखने या ऐसी सूचना या विवरणी देने में असफल रहता है या इन नियमों में से किसी के उपबन्धों का पालन करने में असफल रहता है, वह प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए, जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है :

परन्तु वह नियोजक, जो अद्यतन प्रविष्टियां किए बिना अपेक्षित रजिस्टर या अभिलेख रखता है या अपेक्षित विवरणी देता है या सूचनाएं प्रदर्शित करने में असफल रहता है, जुर्माने से दंडनीय होगा जो दो सौ रुपये तक हो सकता है।"

6. प्ररूप क में, स्तंभ 5 के पश्चात् निम्नलिखित स्तंभ अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6. प्रभावित व्यक्तियों की संख्या।"

[सं० 19/13/68 फैक्० 1/एल आर-4]

New Delhi, the 21st November 1970

S.O. 3845.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal *Cum* Labour Court Jabalpur in the matter

of an application under Section 33A of said Act filed by Shri B. K. Jena of Messrs. Biju Patnaik Mines (Private) Limited, Post Office Barbil, District Keonjhar (Orissa) and their workmen, which was received by the Central Government on the 19th November, 1970.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-*CUM*-LABOUR COURT, JABALPUR

Dated October 24, 1970

CASE NO. CGIT/LC(A)(1) OF 1970

PRESENT:

Shri M. Chandra, Presiding Officer.

PARTIES:

Shri B. K. Jena,—*Complainant.*

Versus

M/s. B. Patnaik Mines (P) Ltd., Barbil—*Opposite Party.*

APPEARANCES:

For the complainant—Shri J. R. Dash, Secretary, I.N.T.U.C. (Orissa Branch).

For the Opposite Party—Sri K. P. A., Gopalkrishnan, Agent.

INDUSTRY: Coal Mine. DISTRICT: Keonjhar (Orissa).

AWARD

This is a complaint by Sri B. K. Jana against M/s. Biju Patnaik Co. Ltd., Barbil (Orissa) under Sec. 33-A of the Industrial Disputes Act.

Briefly stated Sri Jena's case was this.

The employers applied before this Court under Sec. 33(2)(b) of the Industrial Disputes Act for approval of an order of dismissal imposed on him. After hearing the parties the application was rejected by this Court in June, 1970. The complainant reported himself for duty and also sent a registered letter requesting the employers to advice him as to when the complainant should report for duty. But he was not allowed to resume duties. In view of the rejection of the application under Sec. 33(2)(b) of the Industrial Disputes Act the dismissal is inoperative and the complainant claims to be on employment. The complainant accordingly makes a complaint under Sec. 33-A of the Industrial Disputes Act for necessary orders.

The parties have now settled the matter amicably and the management has agreed to reinstate Sri B. K. Jena with continuity of service and full back wages. It was also agreed between the parties that the back wages including allowances admissible to the employee concerned right from the date of his dismissal to the date of his return for duties would be paid by 30th December, 1970. The agreement in writing was verified before the Labour Enforcement Officer (Central), Barbil. The case is accordingly decided in terms of the agreement which is accepted by the Tribunal and will form part of the award. The award is made accordingly

(Sd.) M. CHANDRA,
Presiding Officer.

ANNEXURE

Memorandum of Settlement arrived at between the representative of M/s. B. Patnaik Mines (P) Ltd. and of the workman, Sri B. K. Jena, on 1st September, 1970.

PRESENT:

(1) Sri K. P. A. Gopalakrishnan, Agent, on behalf of M/s B. Patnaik Mines (P) Ltd., P.O. Barbil, Dist. Keonjhar (Orissa).

(2) Sri J. R Dash, representative of Sri B. K. Jena.

Short recital of the case

An application under Section 33(2)(b) of the Industrial Disputes Act was filed by the management of M/s. B. Patnaik Mines (P) Ltd. before the Central Government Industrial Tribunal-*cum*-Labour Court, Jabbalpur on 15th April, 1970. The

said Tribunal after hearing the parties *vide* its Order No. CGIT/LC(B)(1)/70 dated 6th July, 1970 rejected the aforesaid application. On receipt of the aforesaid order of the Tribunal, the concerned workman wrote to the Agent as to when he should report himself for duty. In reply, the Agent of M/s B. Patnaik Mines (P) Ltd. informed the concerned workman *vide* his letter No. T/70/2450 dated 24th July, 1970 that the management was contemplating to move a Writ Petition in the Calcutta High Court. The concerned workmen then filed an application to the Central Government Industrial Tribunal-*cum*-Labour Court, Jabbalpur under Section 33-A of the Industrial Disputes Act on 9th August, 1970. The aforesaid application is now pending before the Authority. The Tribunal summoned the parties at Allahabad *vide* its Notice No. GIT/LC(A)(1)/70 dated 20th August, 1970 on 11th September, 1970.

The parties sat together and arrived at the following terms:—

1. That Sri B. K. Jena shall be reinstated by 25th September, 1970 with continuity of service and back wages.

2. The employer shall pay the arrears of monthly salaries and allowances, as admissible to him (B. K. Jena), while in employment, from the date of his dismissal to the date of his reporting for duty. If he fails to report himself for duty by the scheduled date, the workman concerned shall forfeit the claim of his employment.

3. The arrears as per Cl. 2 above shall be paid by 31st December, 1970.

The parties agreed to the above terms of settlement as a gesture of good-will and in the interest of good employer-employee relationship.

In view of this mutual settlement, the parties pray that the learned Tribunal-*cum*-Labour Court, Jabbalpur passes an Order accordingly.

K. P. GOPALAKRISHNAN,
Agent,
M/s. B. PATNAIK Mines (P) Ltd.
Barbil.

J.R. DASH,
Representative of
Sri B. K. Jena,
Barbil.

Witness:—

1. S. K. DEB,
Labour Enforcement Officer (C),
Barbil.

2. S. URAM,
L.D.C.
Office of the LEO(C), Barbil.

B. K. JENA,
the Concerned Workmen.

Dated, Barbil, the 24th September, 1970.

PART OF AWARD

M. CHANDRA,
Presiding Officer,
Industrial Tribunal-*cum*-Labour Court,
(Central) Jabalpur.

[No. 12(33)/70/LRIV.]

New Delhi, the 25th November 1970

S.O. 3846.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 3), Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the Bhowra Colliery of Messrs Karamchand Chand Thapar and Brothers (Private) Limited, Central Office Bhowra, Post Office Bhowra (Dhanbad) and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th November, 1970.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, AT DHANBAD

REFERENCE NO. 31 OF 1969

PRESENT:

Shri Sachidanand Sinha, M.A.M.L., Presiding Officer.

PARTIES:

Employers in relation to the management of Bhowra Colliery.

AND

Their workmen.

APPEARANCES:

For Employers.—Shri K. C. Nandkeolyar, Dy. Chief Personnel Officer.

For Workmen.—Shri Ram Mitra, Secretary, Bihar Koyala Mazdoor Sabha.

INDUSTRY: Coal. STATE: Bihar.

Dhanbad, Dated the 4th November 1970

AWARD

1. The Central Government, being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bhowra Colliery of M/s. Karamchand Thapar and Brothers (P) Limited, Central office Bhowra, P. O. BHOWRA District Dhanbad and their workmen, by its order No. 1/15/68-LR.II dated the 30th April, 1969, referred to this Tribunal under Section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication the dispute in respect to the matters specified in the schedule annexed thereto. The schedule is extracted below:

SCHEDULE

"Whether the claim of the following Coal Cutting Machine Helpers of Bhowra Colliery of Messrs Karamchand Thapar and Brothers (Private) Ltd., Central Office Bhowra, Post Office Bhowra (Dhanbad), for the Wage rate of Category IV, as per recommendations of the Central Wage Board for the Coal Industry, is justified? If so, to what relief and from which date are these workmen entitled?

Sl. No.	*Name of the workmen*
1.	Priti Singh.
2.	Balmiki Singh.
3.	Bhairu Shaw.
4.	Ram Prasad Koiry.
5.	Gulab Singh.
6.	Satyaban Karmakar.
7.	Sokot Mahato.
8	Kedar Gosai.
9.	Makhan Bauri.
10.	Ajodhya Singh.
11.	Monjoor Gorh.
12.	Bhukhal Harijan."

2. Shri R. Mitra, Secretary, Bihar Koyala Mazdoor Sabha filed written statement, for and on behalf of the workmen, on the 8th July, 1969, and the employers filed their written statement on the 18th November, 1969.

3. It is not necessary to state the respective stand of each party as the dispute has been settled amicably through a compromise. The joint petition of compromise which has duly been verified by Shri R. Mitra, Secretary, Bihar Koyala Mazdoor Sabha for and on behalf of the workmen and by Shri J. R. Sharma, Agent for and on behalf of the employers, has been filed before this Tribunal on the 3rd November, 1970 by Sri K. C. Nandkeolyar, Deputy Chief Personnel Officer of the Colliery Company.

4. According to the terms and conditions of compromise the workmen concerned mentioned in serial 4, 7, 8, 9, 10 and 12 of the Schedule of reference *i.e.* namely Sarvasri Ram Prasad Koiry, Sokat Mahato, Kedar Gosai, Makhan Bauri, Ajodhya Singh and Bhukhal Harijan have been placed in the Category IV with effect from 15th August, 1967 and they will receive lump-sum amounts as mentioned in the memorandum of compromise, towards their arrear dues. As regards

remaining six concerned workmen mentioned in serial 1, 2, 3, 5, 6, and 11 it has been stated that they had earlier compromised their demands with the management as per settlement made under section 12(3) of Industrial Dispute Act before the A.L.C.(C), Dhanbad II on the 25th April, 1970.

5. I find hat the terms are reasonable, justified and acceptable and accordingly pass my award in terms of the Memorandum of Settlement a copy of which is enclosed herewith as Annexure 'A'.

This is my award. It may now be submitted to the Central Government under section 15 of the Industrial Dispute Act, 1947.

(Sd.) SACHIDANAND SINHA,
Presiding Officer.

ANNEXURE 'A'

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 3—DHANBAD.

REFERENCE NO. 31/1969

PARTIES:

Employers in relation to Bhowra Colliery.

AND

Their Workmen, represented by Bihar Koyla Mazdoor Sabha.

Joint petition for compromise on behalf of the parties.

* * * * * *

The parties above named beg to submit as follows:—

That, the Central Government has referred the cases of the following 12 Coal cutting machine mazdoors for adjudication before this Hon'ble Tribunal, *vide* their letter No. 1/15/68-LR-II.

1. Prithi Singh.
2. Balmiki Singh.
3. Bhairo Shaw.
4. Ram Prasad Koiri.
5. Gulab Singh.
6. Satyaban Karmakar.
7. Sokat Mahato.
8. Kedar Gossain.
9. Makhan Bauri.
10. Ajodhya Singh.
11. Majur Gorh.
12. Bhukhal Harijan.

That, the following Six workers namely.—1. Prithi Singh Serial No. 1, Balmiki Singh Serial No. 2, Bhairo Shaw Serial No. 3, Gulab Singh, Serial No. 5, Satyaban Karmarkar, Serial No. 6, and Majur Gorh, Serial No. 11, have already compromised their demands with the Management on the terms as mentioned in the settlement dated 25th April, 1970 U/S 12(3) of the I.D. Act., before the A.L.C. (C), Dhanbad-II copy of which has already been submitted before the Hon'ble Tribunal.

That, the following remaining Six workers namely:—Ram Prasad Koiri, Serial No. 4, Sokat Mahato, Serial No. 7, Kedar Gossain, Serial No. 8, Makhan Bauri, Serial No. 9, Ajodhya Singh, Serial No. 10, Bhukhal Harijan, Serial No. 12, have compromised their demands on the following terms:—

(a) That. the above named workmen are placed in Cat. IV with effect from 15th August, 1967.

(b) That. they will get the following amount as lump sum against their arrears, as mentioned against each name:—

1. Ram Prasad Koiri	Rs.	625.10
2. Sokat Mahato	Rs.	719.72
3. Kedar Gossain	Rs.	697.52
4. Makhan Bauri	Rs.	565.60
5. Ajodhya Singh	Rs.	655.44
6. Bhukhal Harijan	Rs.	543.47

(c) That, the parties will bear their own cost.

That, the above mentioned terms of settlement may kindly be held as reasonable and justified and Award passed accordingly.

And for this act of kindness your petitioners as in duty bound shall ever pray.

Sd./ RAM MITRA,
For Workmen
Secretary, B. K. M. S.

(Sd.) Illegible
For Employers.
Agent

Workers:—

1. Ram Prasad Koiri.
2. Sokat Mahato.
3. Kedar Gossain.
4. Makhan Bauri.
5. Ajodhya Singh.
6. Bhukhal Harijan.

[No. 1/15/68-LR.II]

S.O. 3847.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Kajora Colliery of Messrs Western Kajora Collieries (Private) Limited, Post Office Raniganj, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th November, 1970.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA.

REFERENCE No. 39 OF 1970

PARTIES:

Employers in relation to the management of Western Kajora Colliery of Messrs Western Kajora Collieries (Private) Limited

AND

Their workmen.

PRESENT:

Mr. B. N. Banerjee—Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of the Empoyers } Absent.
On behalf of the workmen }

STATE: West Bengal INDUSTRY: Coal Mines

AWARD

By Order No. 1/30/70-LRII, dated August 4/6, 1970, the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred the following dispute between the employers in relation to the management of Western Kajora Colliery of Messrs Western Kajora Collieries (Private) Limited and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:—

"Whether the management of Western Kajora Colliery of Messrs Western Kajora Collieries Private Limited Post Office Raniganj, District Burdwan was justified in retrenching Sarvashri Anandi Nunia, Ramai Harijan, Kitra Bind, Muni Bind, Bhado Bind, Kishun Lal Sinha, Ramlal Harijan, Jugal Bind, Giridhari Nunia, Etwari Roy, Mongal Bind, Saithan Bind, Ramater Jha, Harppad Pal (No. 2), all Under Ground Trammers, Anil Gope, Surface Trammer, Sultan Mia, Driller, from the 13th April, 1970? If not, to what relief are they entitled?"

2. Both the management and the workmen adopted a strange attitude of non-cooperation with this Tribunal. They did not file their respective written statement, although served with notices to do so within a given time. They did not also apply for extension of time to file written statements. The management did not appear on the date fixed for settling a date of hearing. Mr. Kalyan Sankar Roy appeared on behlf of the Colliery Mazdoor Sabha, which had espoused the cause of the workmen, representing the workmen. A peremptory date of hearing was fixed after hearing Mr. Kalyan Sankar Roy and November 10, 1970 was that date. I set out hereinbelow the order passed on that date:—

"Nobody appears on behalf of the management. Sri Kalyan Sankar Roy appears on behalf of the workmen.

To November 10, 1970 for peremptory date of hearing. Parties must file their documents, if any, before the date fixed for hearing, with a list of documents filed served on the other side. Parties must come ready with their witnesses on the date fixed for hearing. No adjournment will be granted on that date.

Inform management by registered post."

A copy of the order was forwarded to the management by Registered post.

3. On 9th November, 1970, one day prior to the peremptory date of hearing, there was a telegram received couched in the following language:—

"PRAY ADJOURNMENT FOR REFERENCE NUMBER 39 OF 1970 REGARDING WESTERN KAZORA COLLIERY DUE TO THE SERIOUS ILLNESS OF ORGANISING SECRETARY WHO IS DEALING WITH THE CASE—KISHORI GIRI OFFICE SECRETARY COLLIERY MAZDOOR SABHA ASANSOL."

On that telegram I recorded the following order:

"No action need be taken unless a formal application be moved, when the matter will be considered on merits."

The reason why I am reluctant to proceed on telegraphic prayers for adjournment may be recorded here. There has been occasions, in the past, when such telegrams have proved to be practical jokes cut upon the Tribunal, nobody taking responsibility for such a telegram received. By taking notice of such telegrams and proceeding thereupon, this Tribunal becomes embarrassed. Insistence is, therefore, made upon an application to be moved before this Tribunal, by somebody duly authorised. In this particular case, the application was not made by Mr. Kalyan Sankar Roy, who had filed an authorisation on behalf of the Colliery Mazdoor Sabha, nor was the application made by the Organising Secretary of the Colliery Mazdoor Sabha or any of the office-bearers thereof, who might represent the workmen under Section 36 of the Industrial Disputes Act. The telegram appears to have been made by the Office Secretary of Colilery Mazdoor Sabha, a designation with which I am not acquainted and his authority to represent the workmen is highly doubted. I, therefore, ignore the prayer for adjournment made on behalf of the workmen.

4. On the date of hearing, there was a telegram received from the Manager, Western Kajora Colliery couched in the following language:—

"MINE WORKING SUSPENDED LABOUR TROUBLE EXCISTS PRAY ADJOURNMENT FOR REFERENCE NO. 37 AND 39 OF 1970: MANAGER WESTERN KAJORA COLLIERY"

Reference No. 37, I need observe, was disposed off yesterday. This telegram is too late so far as that reference is concerned. So far as the present reference is concerned, I have already recorded my reason why I am disinclined to proceed on the basis of telegraphic prayers for adjournment.

5. There is an additional reason why I am disinclined to grant any adjournment whatsoever in this matter. Neither party cared to file even their written statement or to file their documents. Excepting on one occasion when Mr. Kalyan Sankar Roy appeared on behalf of the workmen, on the date of settling a peremptory date of hearing, nobody cooperated with this Tribunal and the management was throughout conspicuous by their absence.

6. In these circumstances, I am of the opinion that neither party is serious about the dispute which is pending before the Tribunal. Neither party even cared to disclose what period of adjournment would be sufficient for their respective purposes. I am not prepared to wait indefinitely and await the convenience of parties.

I, therefore, record a 'no dispute' award in this matter.

Dated, November, 10, 1970.

Sd. B. N. BANERJEE,
Presiding Officer.

[No. 1/30/70-LR.II.]

S.O. 3848.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. 3) Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of East Bastacolla Colliery belonging to East Bastacolla Colliery Company, Post Office Jharia, District, Dhanbad, and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th November, 1970.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-*CUM*-LABOUR COURT NO. 3, AT DHANBAD.

REFERENCE No. 2 OF 1970

PRESENT:

Shri Sachidanand Sinha, M.A.M.L., Presiding Officer.

PARTIES:

Employers in relation to the management of East Bastacolla Colliery,

AND

Their workmen.

APPEARANCES:

For Employers—Shri P. Burman, Advocate.
For Workmen—None.

INDUSTRY: Coal STATE: Bihar.

Dhanbad, dated the 7th November, 1970

AWARD

1. The Central Government, being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of East Bastacolla Colliery belonging to East Bastacolla Colliery Company, and their workmen by its order No. 2/151/69-LRII dated the 17th November, 1969, referred to this Tribunal under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication the dispute in respect to the matters specified in the schedule annexed thereto. The schedule is extracted below:—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of East Bastacolla Colliery belonging to East Bastacolla Colliery Company, Post Office Jharia, District Dhanbad, in dismissing Shri Mohammed Alim, Trammer with effect from the 12th July, 1969 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The Secretary, Krantikari Koyala Mazdoor Sangh filed the written statement, for and on behalf of the workmen, on the 23rd February, 1970 and the employers filed their written statement on the 27th January, 1970.

3. On 4th November, 1970 the date fixed for hearing in the matter Shri P. Burman, Advocate appeared on behalf of employers and submitted that the workman concerned was no more interested in his claim for re-instatement and that he had accepted a sum of Rs. 300 only towards full and final settlement of his claim and that the said amount was accordingly paid to him by the employers in presence of the Union's representative. Shri Burman further submitted that there was no more dispute between the parties and thus prayed for a 'No dispute' award in the matter. Shri Burman also filed a written petition to the above effect which has been signed by Shri. H. K. Qha, Manager of East Bastacolla Colliery for and on behalf of the employers and by Shri S. K. Rai, General Secretary of Krantikari Koyala Mazdoor Sangh for and on behalf of the workmen and witnessed by Shri P. Burman, Advocate himself.

4. In view of the above facts I hold that the dispute has been settled by the parties between themselves and that they are no more interested in persuing the matter any further. There exists no more dispute and hence I make my award accordingly.

5. This is my award. It may be submitted to the Central Government under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Sd.) SACHIDANAND SINHA,
Presiding Officer.

[No. 2/151/69-LR.II.]

S.O. 3849.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of East Nimcha Colliery, Post Office Jaykaynagar, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th November, 1970.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CALCUTTA

REFERENCE No. 41 OF 1970

PARTIES:

Employers in relation to the management of East Nimcha Colliery.

AND

Their workmen.

PRESENT:

Mr. B. N. Banerjee,—Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers—Sri Gunabantrai Upadhaya, Assistant Labour Officer.

On behalf of Workmen—Absent.

STATE: West Bengal. INDUSTRY: Coal Mines.

AWARD

By Order No. 6/20/70-LRII, dated August 20, 1970, the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred the following dispute between the employers in relation to the management of East Nimcha Colliery and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:—

> "Whether the management of East Nimcha Colliery, Post Office Jaykaynagar District Burdwan was justified in terminating the services of Sarvashri Ajit Singh, Overman, Ramjee Singh, Overman, Bhairab Singh, Mazdoor Sirdar, Surendra Sharma, Lamp Room Incharge, Raghubans Misra, Coal Cutting Machine Fitter, Birbal Mallah, Body Checker, Mohammad Sadique Khan, Loader, Rameswar Sharma, Pit Munshi, Ramchandra Sharma, Bill Clerk, Bankateswar Singh, Office Clerk, Sachitanand Singh, Attendance Clerk, Upendra Singh, Bill Clerk, Mahesh Prasad Sharma, Banker Munshi, Rabindra Kumar Sharma, Pit Munshi, Ram Naresh Singh, Workshop Fitter, Naresh Singh, Loco Driver, Sudhakar Roy, Loco Driver, Lahari Singh, Night Guard, Krishnanand Sharma, Haulage Khalasi, Hardeo Singh, Banker Checker, Jagannath Singh, On-setter, Madan Dhari Singh, Banksman, Ram Chandra Dusad, Surface Trammer, Sitaram Paswan, Surface Trammer, Suresh Singh, Coal Cutting Machine Fitter and Maheswar Dayal Chaturbedi, Munshi of East Nimcha Colliery from the 13th February, 1970? If not, to what relief are these workmen entitled?"

2. Both the management and the workmen, whose cause had been taken up by Colliery Mazdoor Congress (HMS), filed their respective written statement. It is not, however, necessary for me to go into the merits of the respective case because the parties did not want further to pursue the dispute and filed a petition of compromise embodying the terms of settlement.

3. The terms of settlement deal with all the workmen, named in the Schedule to the Order of Reference, excepting the following:

(a) Ram Chandra Dusad, Surface Trammer

(b) Sitaram Paswan, Surface Trammer, and

(c) Suresh Singh, Coal Cutting Machine Fitter.

This is, however, not a matter of consequence because the opening words of the petition of settlement state:

> "The instant industrial dispute has been mutually discussed between the parties and the same has been amicably settled between them on the following terms."

Thus, the position is clear that the entire dispute has been settled without any relief to the three workmen named above. In any event, those three workmen did not appear to be further interested in the dispute. They did not appear at any stage of the proceeding, not did they appear before me to-day, which was fixed as the peremptory date of hearing. Therefore, they must be no longer interested in the dispute.

4. Since the dispute has been settled between the parties, I record the settlement and pass an award in terms of the settlement. Let the petition of compromise form part of this award.

(Sd.) B. N. BANERJEE,
Presiding Officer.

Dated, November 11, 1970

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

IN THE MATTER OF REFERENCE NO. 41 OF 1970.

PARTIES:

Employers in relation East Nimcha Colliery of M/s. The East Laikdih Colliery Co. (P) Ltd., P.O. Jaykayanagar, Distt. Burdwan (West Bengal),

Vrs.

Their workmen represented by the Colliery Mazdoor Congress (H.M.P.), P.O. Asansol, Distt. Burdwan (West Bengal).

Representing the employers.—1. Shri R. C, Patel Director, M/s, The East Laikdih Colliery Co. (P) Ltd.

2. Shri M. C. Saini, Agent, East Nimcha Colliery.

3. Shri B. P. Dabral, Chief Personnel Officer, M/s. The East Laikdih Colliery Co. (P) Ltd.

Representing the workmen.—1. Shri T. N. Shukla, General Secretary, Colliery Mazdoor Congress (HMP), Asansol.

2. Shri Vinaya Kumar, Joint Secretary, Colliery Mazdoor Congress (HMP), Asansol.

The representative of the employers and the workmen submit as under:—

The instant industrial dispute has been mutually discussed between the parties and the same has been amicably settled between them on the following terms:—

Terms of Settlement

(1) (i). *It is agreed that the management of East Nimcha Colliery of M/s.* The East Laikdih Colliery Co. (P) Ltd., P.O. Jayakayanagar, Distt. Burdwan (hereinafter referred to as the management) shall provide employment to the workmen named below at East Nimcha Colliery with effect from 1st October, 1970 with continuity of service:—

1. Shri Ajit Singh Saini.
2. Shri Bhairoo Singh.
3. Shri Ram Chandran Sharma.
4. Shri Sudhakar Rai.
5. Shri Md. Siddique.
6. Shri Rameshwar Sharma.
7. Shri M. D. Chaturvedi.

(1) (ii) It is agreed that the management of East Nimcha Colliery of M/s. The East Laikdih Colliery Co. (P) Ltd., shall provide employment to the workmen named below at East Nimcha Colliery with effect from 1st November 1970 with continuity of service:—

1. Shri Hardeo Singh.
2. Shri Birbal Mallah.
3. Shri Sachidanand Singh
4. Shri Mahes Sharma.

(1) (iii) It is agreed that the management of East Nimcha Colliery of M/s. The East Laikdih Colliery Co. (P) Ltd., P.O. Jaykayanagar, Distt. Burdwan shall provide employment to the workmen named below at

East Nimcha Colliery with effect from 1st December 1970 with continuity of service:—

1. Shri Raghuvansh Mishra.
2. Shri Krishnanand Sharma.
3. Shri Surendra Sharma.
4. Shri Jagan Nath Singh.

(1) (iv) It is agreed that the intervening period from 24th September 1969 to the date of actual resumption of duties of the fifteen workmen named above shall be treated as leave without wages.

(2) (i) With regard to the remaining eight workmen named below it is agreed between the parties that there being no immediate vacancies for their absorption, the parties will have mutual discussion with a view to exploring the possibility of their absorption as early as possible but in any case not later than four months from date.

1. Shri Naresh Singh.
2. Shri Ramji Singh.
3. Shri Ravindra Kumar Sharma.
4. Shri Lahuri Singh.
5. Shri Venkatesh Singh.
6. Shri Madan Dhari Singh.
7. Shri Ram Naresh Singh.
8. Shri Upendra Singh.

(2) (ii) It is agreed that in case the parties fail to arrive at an amicable settlement in this regard within four months from date, they shall jointly refer the matter to the arbitration of Shri O. Venkatachalam, Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi or any other officers acceptable to both the parties under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947.

The representatives of both parties submit that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept the above terms of the settlement and pass his award in terms of the settlement referred to above.

(Sd.) R. C. PATEL, 30-9-1970.
(Sd.) H. C. SAINI, 30-9-1970.
(Sd.) B. P. DABRAL, 30-9-1970.
Representing the employers

(Sd.) T. N. SHUKLA, 30-9-1970.
(Sd.) VINAYA KUMAR. 30-9-1970.
Representing the workmen.

Witnesses:

1. (Sd.) K. SHARAN. 30-9-1970.
Regional Labour Commissioner (C), Asansol.
2. (Sd.) R. B. MAZUMDAR, 30-9-1970.
Assistant Labour Commissioner (C), Asansol.

Asansol, the 30th September, 1970.

[No. 6/20/70-LR.II.]

S.O. 3850.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Kajora Colliery Post Office Raniganj, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th November, 1970.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

REFERENCE NO. 37 OF 1970

PARTIES:
Employers in relation to the management of Western Kajora Colliery,

AND

Their workmen.

PRESENT:
Mr. B. N. Banerjee, Presiding Officer.

APPEARANCES:
On behalf of Employers Absent

On behalf of Workmen

STATE: West Bengal. INDUSTRY: Coal Mines.

AWARD

By Order No. 6/23/70-LRII, dated August 12, 1970, the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred the following industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Kajora Colliery and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:—

"Whether the management of Western Kajora Colliery, Post Office Raniganj, District Burdwan was justified in retrenching Sarvashri Puran Kumar Mondal and Raju Paswan, Underground Trammers with effect from the 13th April, 1970 and if not, to what relief they are entitled?"

2. The management filed a written statement. The workmen did not. The workmen did not appear even on the date fixed for settling a peremptory date of hearing, in spite of notice. Today, which was fixed as the peremptory date of hearing, neither the management nor the workmen appeared. It appears from the written statement filed by the management that the dispute which was referred to this Tribunal was settled by agreement and the two concerned workmen, who had been re-retrenched, were re-employed with continuity of service. This may explain why neither the management nor the workmen are interested in the hearing of the reference any longer.

3. Since nobody seems to be interested in the reference, I pass a 'no dispute' award in the matter.

(Sd.) B. N. ABNERJEE, Presiding Officer.

Dated November 9, 1970

[No. 6/23/70-LR.II.]

S.O. 3851.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Electrical and Mechanical Workshop of National Coal Development Corporation Limited, Darbhanga House, Ranchi and their workmen represented by Madhya Pradesh Colliery Workers' Federation, Post Office Chirimiri, District Surguja (Madhya Pradesh);

And whereas the said employers and their workmen have by a written agreement, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), referred the said dispute to arbitration by the persons specified therein, and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement.

Regd. A/D

FORM C

[Under Rule 6 of Industrial Disputes (Central) Rules]

AGREEMENT

(Under Sec. 10-A of the I. D. Act, 1947)

Name of parties:—

Representing employers:—1. Sri I. B. Sanyal, Chief Personnel Officer, National Coal Development Corporation Limited, Darbhanga House, Ranchi.

Representing workmen:—1. Sri B. N. P. Sinha, Organising Secretary, M. P. Colliery Workers Federation, P.O. Chirimiri, Dist. Surguja, Madhya Pradesh.

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Sri M. B. Tawadey, Chief Engineer (E&M), NCDC Ltd., Ranchi and Sri H. Srinivasan, Chief Engineer (Excavation) NCDC Ltd., Ranchi.

1. *Specific matter in dispute.*—Whether the demand of the Union for the redesignation of the post of Laboratory Assistant in the Central Electrical and Mechanical Workshop, Korba as Research Assistant is justified (it being understood that there will be no change in the pay scale or the duties etc. of the post).

2. *Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.*—(i) Employers: National Coal Development Corporation Ltd., Central Elecrical & Mechanical Workshop, Korba, P. O. Korba Colliery, Dist. Surguja, M.P.

(ii) Workmen represented by:

1. M. P. Colliery Workers Federation P. O. Chirimiri, Dist. Surgujja, M.P:

3. *Name of the union, if any representing the workmen in question.*—Details given against column (2) above.

4. *Total number of workmen employed in the undertaking affected.*—About 400

5. *Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.*—1.

We further agree that the decision of the Arbitrators shall be binding on us. In case, the Arbitrators were equally divided in their opinion, the matter shall be referred by them for the decision of Sri R. Sinha, Director (Admn), National Coal Development Corporation Limited, Ranchi who will function as the Umpire and whose award shall be binding on us.

The Arbitrators or the Umpire, as the case may be, shall make their award within a period of 6 months from the date on which this agreement is published in the Gazette of India or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period mentioned above, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the Parties
(Sd.) I. B. SANYAL,
Chief Personnel Officer,
National Coal Development Corporation Limited, Darbhanga House, Ranchi
(Sd.) B. N. P. SINHA,
Organising Secy.
M. P. Colliery Workers' Federation
P.O. Chirimiri, Dist. Surguja, M.P.

(Sd.) SUKHLALL SINGH, Secy.
M.P. Colliery Workers' Federation,
P.O. Chirimiri, Dist. Surguja, MP:

Dated at Ranchi this 7th day of September 1970

Witnesses:—
1. Illegible.
2. Illegible.

[No. 8/175/70-LRII.]

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1970

का० आ० 3851.—यतः राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, दरभंगा हाऊस, रांची की इलैक्ट्रिकल एंड मेकैनिकल वर्कशाप के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन, डाकघर, चिरिमिरी, जिला, सुरगूजा (मध्य प्रदेश) करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः उक्त नियोजकों और उनके कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति के माध्यस्थम के लिये निर्देशित कर दिया है और उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को एतद्द्वारा प्रकाशित करती है

प्रारूप ग

(औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) निगम के नियम 6 के अधीन)

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन) करार

पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : 1. श्री आई० बी० सान्याल
मुख्य कार्मिक अधिकारी, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, दरभंगा हाऊस, रांची ।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1. श्री बी० एन० पी० सिन्हा,
संगठन सचिव,
एम० पी० कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन, डाकघर चिरिमिरी, जिला सुरगुजा, मध्य प्रदेश ।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को एतद्द्वारा श्री एम० बी० तवाडे, मुख्य इंजीनियर (ई० एंड० एम०), राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची और श्री एच० श्रीनिवासन, मुख्य इंजीनियर (एक्सकैवेशन), राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची के माध्यस्थम् के लिये निर्देशित करने का करार किया गया है ;

1. **विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय :** क्या सैंट्रल इलैक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वर्कशाप, कोर्बा, में प्रयोगशाला सहायक के पद को अनुसंधान सहायक के रूप में पुनः पदनामित करने की संघ की मांग न्यायोचित है समझ लिया गया है कि इस पद के वेतन-मान या कर्तव्यों आदि में कोई परिवर्तन नहीं होगा)

2. **विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अन्तर्वलित स्थापना या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है ।** (I) नियोजक : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, सैन्ट्रल इलैक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वर्कशाप, कोर्बा, डाकघर कोर्बा कोलियरी, जिला सुरगूजा, मध्य प्रदेश ।

(II) कर्मकार, जिनका प्रतिनिधित्व एम० पी० कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन, डाकघर चिरिमिरी, जिला सुरगूजा, मध्य प्रदेश करती है ।

3. **यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम** ऊपर स्तम्भ (2) के सामने ब्यौरा दे दिया गया है ।

4. **प्रश्नगत उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या ।** लगभग 400

5. विवाद द्वारा प्रभावित या सम्मान्यतः होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या—

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थों का विनिश्चय हम पर आबद्धकर होगा । यदि मध्यस्थ अपनी राय में बराबर बटे हुए हों, तो उनके द्वारा यह मामला श्री आर० सिन्हा, निदेशक (प्रशासन), राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची के विनिश्चिय के लिए निर्देशित किया जायेगा, जो अधिनिर्णायक के रूप में कार्य करेगा और जिसका पंचाट हम पर आबद्धकर होगा ।

मध्यस्थ या अधिनिर्णायक जैसी भी स्थिति हो, अपना पंचाट इस करार के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से छः मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा : यदि पंचाट अपरवर्णित कालावधि के भीतर नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिये निदेश स्वतः रद्द हो जायगा और हम नए माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने की स्वतंत्र होंगे ।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

ह /
आई० बी० सान्याल,
मुख्य कार्मिक अधिकारी,
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड,
दरभंगा हाऊस, रांची ।

ह०
बी० एन० पी० सिन्हा,
संगठन मंत्री,
एम० पी० कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन,
डाकघर चिरिमिरी,
जिला सुरगुजा (मध्य प्रदेश) ।

ह०
सुखलाल सिंह,
मंत्री,
मध्य प्रदेश कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन,
डाकघर, चिरिमिरी,
जिला सुरगजा, मध्य प्रदेश ।

रांची, तारीख : 7 सितम्बर, 1970

साक्षी

1. ह०
2. ह०

[सं० 8/175/70—एल०आर०—2]

S.O. 3852.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Electrical and Mechanical Workshop of National Coal Development Corporation Limited, Darbhanga House, Ranchi and their workmen represented by Madhya Pradesh Colliery Workers' Federation, Post Office Chirimiri, District Surguja (Madhya Pradesh);

And whereas the said employers and their workmen have by a written agreement, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), referred the said dispute to arbitration by the persons specified therein, and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement.

Regd. A/D

FORM C

[Under Rule 6 of Industrial Disputes (Central) Rules]

AGREEMENT

(Under Sec. 10-A of the I.D. Act, 1947)

Name of parties:—

Representing employers:—1 Sri I. B. Sanyal, Chief Personnel Officer, National Coal Development Corporation Limited, Darbhanga House, Ranchi.

Representing workmen.—1. Sri B. N. Sinha, Organising Secretary, M.P. Colliery Workers' Federation, P.O. Chirimiri, District Surguja, M.P.

It is hereby agreed between the parties to refer to following industrial dispute to the arbitration of Sri M. B. Tawadey. Chief Engineer (E&M), NCDC Ltd. Ranchi and Sri Srinivasan, Chief Engineer (Excavation), NCDC Ltd., Ranchi.

1. *Specific matter in dispute.*—Whether the demand of the Union for promotion of Sri S. C. Bhattacharjee, Electrical Fitter of Central Electrical and Mechanical Workshop, Korba to the post of Chargeman) or other benefits is justified. If so, to what relief he is entitled?

2. *Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.*- (1) Employers: National Coal Develop-Development Corporation Limited, Central Electrical and Mechanical Workshop, Korba, P.O. Korba colliery, Dist. Surgujja, M.P.

(ii) Workmen represented by:

1. M.P. Colliery Workers' Federation, P.O. Chirimiri, District Surguja, M.P.

3. *Name of the union, if any representing the workmen in question.*—Details given against column (2) above.

4. *Total number of workmen employed in the undertaking affected.*—About 400.

5. *Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.*—1

We further agree that the decision of the Arbitrators shall be binding on us In case, the Arbitrators were equally divided in their opinion, the matter shall be referred by them for the decision of Sri R. Sinha, Director (Admn.), National Coal Development Corporation Limited, Ranchi who will function as the Umpire and whose award shall be binding on us.

The Arbitrators or the Umpire, as the case may be, shall make their award within a period of 6 months from the date on which this agreement is published in the Gazette of India or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period mentioned above, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the Parties

(Sd.) I. B. SANYAL,
Chief Personnel Officer.
National Coal Development Corporation Ltd., Darbhanga House, Ranchi.

(Sd.) SUKHLALL SINGH,
Secretary,
Madhya Pradesh Colliery
Workers' Federation,
P.O. Chirimiri,
Dist. Surguja, M.P.

B. N. P. SINHA,
Organising Secy.
M. P. Colliery Workers' Federation
P. O. Chirimiri, Dist. Surguja, MP

Dated at Ranchi
This 7th day of September, 1970.

Witnesses:—

1. Braj Narain Pd.

2. P. Venugopal.

[No. 8/176/70-LRII.]

का० आ० 3852.—यतः राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, दरभंगा हाऊस, रांची की इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकैनिकल वर्कशाप के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन, डाकघर चिरिमिरी, जिला सुरगूजा (मध्य प्रदेश) करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः उक्त नियोजकों और उनके कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित कर दिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को एतद्द्वारा प्रकाशित करती है।

(करार)

प्ररूप ग

[औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम के नियम 6 के अधीन]

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

करार

पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले :

1. श्री आई० बी० सान्याल, मुख्य कार्मिक अधिकारी, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, दरभंगा हाऊस, रांची।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले :

1. श्री बी० एन० पी० सिन्हा संगठन, सचिव, एम० पी० कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन, डाकघर चिरिमिरी, जिला सुरगूजा, मध्य प्रदेश।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को एतद्द्वारा श्री एम० बी० तवाडे, मुख्य इंजीनियर (ई० एण्ड एम०), राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची और श्री एच० श्री निवासन, मुख्य इंजीनियर (एक्सकैवेशन), राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची के माध्यस्थम् के लिये एतद्द्वारा निर्देशित करने का करार किया गया है।

1. विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय : क्या सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मकैनिकल वर्कशाप, कोर्बा के इलैक्ट्रिकल फिटर, श्री एस० सी० भट्टाचार्जी को चार्जमैन के पद पर प्रोन्नत करने या अन्य फायदों की संघ की मांग न्यायोचित है ? यदि हां, तो वह किस अनतोष का हकदार है ?

2. विवाद के पक्षकारों का विवरण; जिसमें अन्तर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है। (i) नियोजक: राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, सेन्ट्रल इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकैनिकल वर्कशाप, कोर्बा, डाकघर कोर्बा कोलियरी, जिला सुरगूजा, मध्य प्रदेश।

(ii) कर्मकार, जिनका प्रतिनिधित्व एम० पी० कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन, डाकघर चिरिमिरी, जिला सुरगूजा, मध्य प्रदेश करती है।

3. यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो, तो उसका नाम। — ऊपर स्तम्भ (2) के सामने ब्यौरा दे दिया गया है।

4. प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या। — लगभग 400

5. विवाद द्वारा प्रभावित या सभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या।

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्धकर होगा। यदि मध्यस्थ अपनी राय में बराबर बटे हुए हों, तो उनके द्वारा यह मामला श्री आर० सिन्हा निदेशक (प्रशासन), राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा, जो अधिनिर्णायक के रूप में कार्य करेगा और जिसका पंचाट हम पर आबद्ध कर होगा।

मध्यस्थ या अधिनिर्णायक, जैसी भी स्थिति हो, अपना पंचाट इस करार के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से छः मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा। यदि पंचाट ऊपर वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निर्देश स्वतः रद्द हो जायगा और हम नए माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

ह०
आई० बी० सान्याल,
मुख्य कार्मिक अधिकारी,
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड,
दरभंगा हाउस, रांची।

ह०
सुखलाल सिंह
सचिव,
मध्यप्रदेश कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन,
डाकघर चिरिमिरी,
जिला सुरगूजा, मध्य प्रदेश।

ह०
बी० एन० पी० सिन्हा,
संगठन सचिव,
एम० पी० कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन लिमिटेड,
डाकघर चिरिमिरी,
जिला सुरगूजा, मध्य प्रदेश।

तारीख: रांची,
7 सितम्बर, 1970

साक्षी

1. ह०: - -

2. ह०: - -

[सं० 8/176/70-एल० आर०-2]

S.O. 3853.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Elecctrical and Mechanical Workshop of National Coal Development Corporation Limited, Darbhanga House, Ranchi and their workmen represented by Madhya Pradesh Colliery Workers' Federation, Post Office Chirimiri, District Surguja (Madhya Pradesh);

And whereas the said employers and their workmen have by a written agreement, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), referred the said dispute to arbitration by the persons specified therein, and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement.

FORM C

[Under Rule 6 of Industrial Disputes (Central) Rules]

AGREEMENT

(Under Sec. 10-A of the I.D. Act, 1947)

NAME OF PARTIES:

Representing employers.—1. Sri I. B. Sanyal, Chief Personnel Officer, National Coal Development Corporation Limited, Darbhanga House, Ranchi.

Representing workmen.—1. Sri B. N. P. Sinha, Organising Secretary, Madhya Pradesh Colliery Workers Federation, P.O. Chirimiri, District Surguja, M.P.

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Sri M. B. Tawadey, Chief Engineer (E&M), N.C.D.C. Ltd., Ranchi and Sri H. Srinivasan, Chief Engineer (Excv.) N.C.D.C. Ltd., Ranchi.

1. *Specific matter in dispute.*—Whether the grievances of Sri Ravindranath Laboratory Assistant, Central Electrical and Mechanical Workshop, Korba as listed by the union in their letter No. CEMW/KB/MPCWF/10/68-(2) dated 18th September, 1969 addressed to the Assistant Labour Comssioner, Bilaspur, are justified and if so to what relief he is entitled.

2. *Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.*—(i) Employers: National Coal Development Corporation Ltd., Central Electrical and Mechanical Workshop, Korba P.O. Korba Colliery, District Surguja, M.P.

(ii) Workmen as represented by: 1. M. P. Colliery Workers' Federation P.O. Chirimiri, District Surguja, M.P.

3. *Name of the union if any representing the workmen in question.*—Details given against column (2) above.

4. *Total number of workmen employed in the undertaking affected.*—About 100.

5. *Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.*—1.

We further agree that the decision of the Arbitrators shall be binding on us. In case, the Arbitrators are equally divided in their opinion, the matter shall be referred by them for the decision of Sri R. Sinha, Director (Admn.) National Coal Development Corporation Limited, Ranchi who will function as the Umpire and whose award shall be binding on us.

The Arbitrators or the Umpire, as the case may be, shall make their award within a period of 6 months from the date on which this agreement is published in the Gazette of India or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the

period mentioned above, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the Parties:

(Sd.) I. B. SANYAL,
Chief Personnel Officer,
National Coal Development Corporation Ltd.,
Darbhanga House, Ranchi.

(Sd.) SUKHALALL SINGH,
Secretary,
Madhya Pradesh Colliery Workers' Federation,
P.O. Chirimiri, District Surguja, M.P.

(Sd.) B. N. P. SINHA,
Organising Secretary,

Dated at Ranchi, this 7th day of September, 1970.

Witnesses:
1. BRAJ NARAIN PD.
2. P. VENUGOPALA,

No. 8/178/70-LRII.]

का० आ० 3853:—यतः राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, दरभंगा हाऊस, रांची की इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल वर्कशाप के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन, डाकघर चिरिमिरी, जिला सुरगूजा (मध्य प्रदेश) करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः उक्त नियोजकों और उनके कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित कर दिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को एतद्द्वारा प्रकाशित करती है ।

(करार)

प्रारूप ग

(औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम के नियम 6 के अधीन)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

करार

पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : 1. श्री आई बी० सान्याल,
मुख्य कार्मिक अधिकारी,
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड,
दरभंगा हाऊस, रांची ।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : 1. श्री बी० एन० पी० सिन्हा
संगठन सचिव,
मध्य प्रदेश कोलियरी वर्कर्स फडरेशन,
डाकघर चिरिमिरी, जिला सुरगूजा,
मध्य प्रदेश ।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को एतद्द्वारा सर्व श्री एम० बी० तवाडे, मख्य इंजीनियर (ई० एण्ड एम०), राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची और श्री एच० श्री निवासन, मुख्य इजीनियर (एक्सकैवेशन) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची के माध्यस्थम् के लिये एतद्द्वारा निर्देशित करने का करार किया गया है ।

1. विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय :	क्या श्री रविन्द्रनाथ, प्रयोगशाला सहायक सेन्ट्रल इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकैनिकल वर्कशाप, कोर्बा की शिकायतें जो कि सहायक श्रमायुक्त, बिलासपुर को सम्बोधित संघ के पत्र सख्या सी० ई० एम० डब्ल्यू० के० बी /एम० पी० सी० डब्ल्यू० एफ०/10/68–(2), तारीख 18-9-1969 में सूचीबद्ध की गई है, न्यायोचित है और यदि हां, तो वह किस अनुतोष का हकदार है ?
2. विवाद के पक्षकारों का विवरण जिसमें अन्तर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है ।	(i) नियोजक : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, लिमिटेड सैन्ट्रल इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल वर्कशाप, कोर्बा, डाकघर कोर्बा, कोलियरी, जिला सुरगूजा, मध्य प्रदेश । (ii) कर्मकार, जिनका प्रतिनिधित्व एम०पी० कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन, डाकघर, चिरिमिरी, जिला सुरगूजा, मध्य प्रदेश करती है ।
3. यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो, तो उसका नाम ।	उपर स्तम्भ (2) के सामने ब्योरा दे दिया गया है ।
4. प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या ।	लगभग 400
5. विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या ।	124

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्धकर होगा । यदि मध्यस्थ अपनी राय में बराबर बटे हुए हों, तो उनके द्वारा यह मामला श्री आर० सिन्हा, निदेशक (प्रशासन), राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जायगा, जो अधिनिर्णायक के रूप में कार्य करेगा और जिनका पंचाट हम पर आबद्धकर होगा ।

मध्यस्थ या अधिनिर्णायक, जैसी भी स्थिति हो, अपना पंचाट इस करार के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से छः मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा । यदि पंचाट ऊपर वर्णित कालावधि के भीतर नहीं

दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिये निर्देश स्वतः रद्द हो जायगा और हम नए माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे ।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

ह०

आई० बी० सान्याल,
मुख्य कार्मिक अधिकारी,
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड,
दरभंगा हाऊस, रांची ।

ह०
बी० एन० पी० सिन्हा
संगठन सचिव ।
एम० पी० कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन
डाकघर चिरिमिरी, जिला सुरगूजा,
मध्य प्रदेश ।

ह०
सुखलाल सिंह,
सचिव,
मध्य प्रदेश कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन,
डाकघर चिरिमिरी,
जिला सुरगूजा,
मध्य प्रदेश ।
रांची,
तारीख 7 सितम्बर, 1970

साक्षी :

1. ह०.....

2. ह०.....

[संख्या 8/178/70-एल०आर० 2]

S.O. 3854.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Electrical and Mechanical Workshop of National Coal Development Corporation Limited, Darbhanga House, Ranchi and their workmen represented by Madhya Pradesh Colliery Workers' Federation, Post Office Chirimiri, District Surguja (Madhya Pradesh);

And whereas the said employers and their workmen have by a written agreement, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), referred the said dispute to arbitration by the persons specified therein, and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement.

FORM C

[Under Rule 6 of Industrial Disputes (Central)]

AGREEMENT

(Under Section 10-A of the I.D. Act, 1947)

NAME OF PARTIES:—

Representing employers.—1.Sri I. B. Sanyal, Chief Personnel Officer, National Coal Development Corporation Limited, Darbhanga House, Ranchi.

Representing workmen.—1. Sri B. N. P. Sinha, Organising Secretary, Madhya Pradesh Colliery Workers' Federation, P.O. Chirimiri, District Surguja, M.P.

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Sri M. B. Tawadey, Chief Engineer (E&M), N.C.D.C. Ltd., Ranchi and Sri H. Srinivasan, Chief Engineer (Excavation), N.C.D.C. Ltd., Ranchi.

1. *Specific matters in dispute.*—Whether the demand of the Union for recategorisation under the Coal Wage Board's recommendations as accepted by the Government of India, of General Mazdoors (other than Laboratory Assistant) of Central Electrical and Mechanical Workshop, Korba on the basis of the report of the Labour Enforcement Officer (Central), Raipur, vide his letter No. BL-11(343)/69 dated 24th December, 1969 is justified. If so, to what relief they are entitled.

2. *Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment of undertaking involved.*—(i) Employers: National Coal Development Corporation Ltd., Central Electrical and Mechanical Workshop, Korba, P.O. Korba Colliery, District Surguja, M.P.

(ii) Workmen as represented by:—

1. M. P. Colliery Workers' Federation, P.O. Chirimiri, District Surguja, M.P.

3. *Name of the union if any representing the workmen in question.*—Details given against column (2) above.

4. *Total number of workmen employed in the undertaking affected.*—About 400.

5. *Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.*—About 124.

We further agree that the decision of the Arbitrators shall be binding on us. In case, the Arbitrators were equally divided in their opinion, the matter shall be referred by them for the decision of Sri R. Sinha, Director (Admn.), National Coal Development Corporation Limited, Ranchi who will function as the Umpire and whose award shall be binding on us.

The Arbitrators or the Umpire, as the case may be, shall make their award within a period of 6 months from the date on which this agreement is published in the Gazette of India or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period mentioned above, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the Parties

(Sd.) I. B. SANYAL, Secy.
Chief Personnel Officer,
National Coal Development Corporation Limited,
Darbhanga House, Ranchi.

(Sd.) SUKHLALL, SINGH, Secy.
Secretary,
Madhya Pradesh, Colliery Workers' Federation,
P.O. Chirimiri, District Surguja, M.P.

(Sd.) B. N. P. SINHA,
Organising Secretary.

Dated at Ranchi this 7th day of September, 1970

Witnesses:—

1. BRAJ NARAIN PD.

2. P. VENUGOPALA

[No. 8/179/70-LRII.]

का० आ० 3854—यत: राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, दरभंगा हाऊस, रांची की इलेक्ट्रिकल एंड मेकैनिकल वर्कशाप के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व, मध्य प्रदेश कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन, डाकघर चिरिमिरी, जिला सुरगूजा (मध्य प्रदेश) करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यत: उक्त नियोजकों और उनके कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित कर दिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अत:, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को एतद्द्वारा प्रकाशित करती है ।

करार

प्रारूप ग

(औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम के नियम 6 के अधीन)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : 1. श्री आई० बी० सान्याल,
मुख्य कार्मिक अधिकारी,
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड,
दरभंगा हाऊस, रांची ।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : 1. श्री बी० एन० पी० सिन्हा,
संगठन सचिव,
मध्य प्रदेश कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन,
डाकघर चिरिमिरी, जिला सुरगूजा,
मध्य प्रदेश ।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को एतद्द्वारा श्री एम० बी० तवाडे, मुख्य इंजीनियर (ई० एण्ड एम०), राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची और श्री एच० श्रीनिवासन, मुख्य इंजीनियर (एक्सकेवेशन), राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है ।

1. विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय : क्या श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), रायपुर के पत्र संख्या बी०एल०-11(343)/69, तारीख, 24-12-1969 में दी गई रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार द्वारा यथा प्रतिगृहित कोयला मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार सेन्ट्रल इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकैनिकल वर्कशाप कोर्बा के साधारण मजदूरों (प्रयोगशाला सहायक से भिन्न) के पुनर्वर्गीकरण की संघ की मांग न्यायोचित है ? यदि हां, तो वे किस अनुतोष के हकदार हैं ?

2. विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अन्तर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है ।	(i) नियोजक : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, सेन्ट्रल इलेक्ट्रिकल एण्ड मकैनिकल, वर्कशाप, कोर्बा, डाकघर कोर्बा कोलेयरी जिला सुरगूजा, मध्य प्रदेश । ( ) कर्मकार, जिनका प्रतिनिधित्व एम०पी० कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन, डाकघर चिरिमिरी, जिला सुरगूजा, मध्य प्रदेश करती है ।
3. यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो, तो उसका नाम ।	ऊपर स्तम्भ (2) के सामने ब्यौरा दे दिया गया है ।
4. प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या ।	लगभग 400
5. विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या ।	लगभग 124

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्धकर होगा। यदि मध्यस्थ अपनी राय में बराबर बटे हुए हों, तो उनके द्वारा यह मामला श्री आर० सिन्हा, निदेशक (प्रशासन), राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची के विनिश्चय के लिये निर्देशित किया जायेगा जो अधिनिर्णायक के रूप में कार्य करेगा और जिसका पंचाट हम पर आबद्धकर होगा ।

मध्यस्थ या अधिनिर्णायक जैसी भी स्थिति हो, अपना पंचाट इस करार के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से छ : मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा । यदि पंचाट अपर कालावधि के भीतर नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम के लिये निर्देश स्वतः रद्द हो जायेगा और हम नए माध्यस्थम के लिये बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे ।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

आई० बी० सान्याल,
मुख्य कार्मिक अधिकारी,
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड,
दरभंगा हाऊस, रांची ।

ह०
बी० एन० पी० सिन्हा,
संगठन सचिव,
मध्य प्रदेश कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन,
डाकघर चिरिमिरी,
जिला सुरगूजा, मध्य प्रदेश ।

ह०
सुखलाल सिंह,
सचिव,
मध्य प्रदेश कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन,
डाकघर चिरिमिरी,
जिला सुरगूजा, मध्य प्रदेश ।

तारीख :
रांची,
7 सितम्बर, 1970

साक्षी
1. ह० .....
2. ह० .....

ह०
पी० सी० मिश्र

[संख्या 8/179/70-एल०आर०-2]

S.O. 3855.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Electrical and Machanical Workshop of National Coal Development Corporation Limited, Darbhanga House, Ranchi and their Workmen represented by Madhya Pradesh Colliery Workers' Federation, Post Office Chirimiri, District Surguja (Madhya Pradesh);

And Whereas the said employers and their workmen have by a written agreement, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), referred the said dispute to arbitration by the persons specified therein, and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement.

FORM C

(Under Rule 6 of Industrial Disputes (Central) Rules

AGREEMENT

(Under Sec. 10-A of the I.D. Act, 1947)

NAME OF PARTIES:—

Representing employers.—1. Sri I. B. Sanyal, Chief Personnel Officer National Coal Development Corporation Limited Darbhanga House, Ranchi.

Representing workmen.—1. Sri B. N. P: Sinha Organising Secretary Madhya Pradesh Colliery Workers Federation P.O. Chirimiri, Dist. Surguja, MP.

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Sri M. B. Tawadey, Chief Engineer (E&M), NCDC Ltd., Ranchi and Sri H. Srinivasan, Chief Engineer (Excv.), NCDC Ltd., Ranchi.

1. *Specific matter in dispute.*—Whether the demand of the Union for upgradation of the scale of pay of S/Sri B. M. Sharma and S. Goswami Engineer Wrights of Central Electrical and Mechanical Workshop, Korba or for converting them as daily rated mechanics in Category 'A' of Excavation Section is justified. If so, to what relief they are entitled.

2. *Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.*—(i) Employers: National Coal Development Corporation Limited, Central Electrical and Mechanical Workshop, Korba P.O. Korba Colliery, Dist. Surguja, M.P.

(ii) Workmen as represented by:

1. M.P. Colliery Worker's Federation P.O. Chirimiri, District Surguja, M.P.

3. *Name of the union if any representing the workmen in question.*—Details given against column (2) above.

4. *Total number of workmen employed in the undertaking affected.*—About 400.

5. *Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.*—2.

We further agree that the decision of the Arbitrators shall be binding on us. In case, the Arbitrators were equally divided in their opinion, the matter shall be referred by them for the decision of Sri R. Sinha, Director (Admn), National Coal Development Corporation Limited, Ranchi who will function as the Umpire and whose award shall be binding on us.

The Arbitrators or the Umpire, as the case may be, shall make their award within a period of 6 months from the date on which this agreement is published in the Gazette of India or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the

period mentioned above, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the Parties.

(Sd.) I. B. SANYAL, Chief Personnel Officer,
National Coal Development Corporation Limited,
Darbhanga House, Ranchi.

(Sd.) B. N. P. SINHA, Organising Secy.
M.P. Colliery Workers' Federation,
P. O. Chirimiri, District Surguja, MP.

(Sd.) SUKHLAL SINGH, Secy.
Madhya Pradesh Colliery Workers' Federation,
P. O. Chirimiri, District Surguja, MP.

Dated at Ranchi, this 7th Day of September 1970

Witnesses:—

1. BRAJ NARAIN PD.   2. P. VENUGOPAL.

[No. 8/180/70-LR.II.]

का० आ० 3855.—यतः राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड दरभंगा हाऊस, रांची की इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल वर्कशाप के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन, डाकघर चिरिमिरी, जिला सुरगूजा (मध्य प्रदेश) करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः उक्त नियोजकों और उन के कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों केअनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति के माध्यस्थम् के लिये निर्देशित दिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को, एतद्द्वारा है प्राशित करती है।

(करार)

प्ररूप ग

(औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम के नियम 6 के अधीन)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

पक्षकारों के नाम:

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले:   1. श्री आई० बी० सान्याल,
मुख्य कार्मिक अधिकारी,
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड,
दरभंगा हाऊस, रांची।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले:   1. श्री बी0 एन0 पी0 सिन्हा
संगठन सचिव,
मध्य प्रदेश कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन,
डाकघर चिरिमिरी, जिला सुरगूजा,
मध्य प्रदेश।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को एतद्द्वारा श्री एम० बी० लवाडे, मुख्य इंजीनियर (ई० ए०ड एम०), राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची और श्री एच० श्री निवासन मुख्य इंजीनियर (एक्सकेवेशन), राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है ।

1. विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय :	क्या सैन्ट्रल इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकैनिकल वर्कशाप, कोर्बा के इंजीनियर राइटस सर्वश्री बी० एम० शर्मा और एस० गोस्वामी, के वेतनमान को बढ़ाने या उन्हें एक्सकैवेशन अनुभाग के प्रवर्ग 'ए' के दैनिक मजदूरी वाले मेकैनिकों के रूप में बदलने की संघ की मांग न्यायोचित है ? यदि हां, तो वे किस अनुतोष के हकदार हैं ?
2. विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अन्तर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है ।	(i) नियोजक: राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लि० सैन्ट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मेकैनिकल वर्कशाप, कोर्बा, डाकघर कोर्बा कोलियरी, जिला सुरगूजा मध्य प्रदेश । (ii) कर्मकार, जिनका प्रतिनिधित्व एम० पी० कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन, डाकघर चिरिमिरी जिला सुरगूजा, मध्य प्रदेश करती है ।
3. यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम ।	ऊपर स्तम्भ (2) के सामने ब्यौरा दे दिया गया
4. प्रभावित उपक्रम में नियोजन कर्मकारों की कुल संख्या	लगभग 400
5. विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भाव्यत: प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या ।	2

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थों का विनिश्चय हम पर आबद्धकर होगा । यदि मध्यस्थ अपनी राय में बराबर बटे हुए हों, तो उनके द्वारा यह मामला श्री आर० सिन्हा, निदेशक (प्रशासन), राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची के विनिश्चय के लिये निर्देशित किया जायगा, जो ही अधिनिर्णायक के रूप में कार्य करेगा और जिसका पंचाट हम पर आबद्धकर होगा ।

मध्यस्थ या अधिनिर्णायक पूर्व, जैसी भी स्थिति हो, अपना पंचाट भारत के राजपत्र में इस करार के प्रकाशित होने की तारीख से छः मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा । यदि पंचाट ऊपर वर्णित कालावधि के भीतर

नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिये निर्देश स्वतः रद्द हो जायगा और हम नए माध्यस्थम के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे ।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

ह०
आई० बी० सान्याल
मुख्य कार्मिक अधिकारी
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड
दरभंगा हाउस, रांची ।

ह०
सुखलाल सिंह
सचिव ।
मध्य प्रदेश कौलियरी वर्कर्स फेडरेशन,
डाकघर, चिरिमिरी,
जिला सुरगूजा, मध्य प्रदेश ।

ह०
बी० ए० पी० सिन्हा
संगठन सचिव ।
एम० पी० कौलियरी वर्कर्स फेडरेशन लिमिटेड
डाकघर चिरिमिरी,
जिला सुरगूजा, मध्य प्रदेश ।

रांची, तारीख 7 सितम्बर, 1970

साक्षी :

1. ह०.....

2. ह०.....

[संख्या 8/180/70 एल० आर० 2]

S.O. 3856.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Electrical and Machanical Workshop of National Coal Development Corporation Limited, Darbhanga House, Ranchi and their Workmen represented by Madhya Pradesh Colliery Workers' Federation, Post Office Chirimiri, District Surguja (Madhya Pradesh);

And Whereas the said employers and their workmen have by a written agreement, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), referred the said dispute to arbitration by the persons specified therein, and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement.

FORM C

(Under Rule 6 of Industrial Disputes (Central) Rules

AGREEMENT

(Under Sec. 10-A of the I.D. Act, 1947)

NAME OF PARTIES:—

Representing employers.—1. Sri I. B. Sanyal, Chief Personnel Officer National Coal Development Corporation Limited Darbhanga House, Ranchi.

Representing workmen.—1. Sri B. N. P. Sinha, Organising Secretary Madhya Pradesh Colliery Workers Federation P.O., Chirimiri, Dist. Surguja, M.P.

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Sri M. B. Tawadey, Chief Engineer (E&M), NCDC Ltd., Ranchi and Sri H. Srinivasan, Chief Engineer (Excv.), NCDC Ltd., Ranchi.

1. *Specific matter in dispute.*—Whether having regard to the memorandum of settlement dated 14th July 1969 between the Managment of Central Electrical and Mechanical Workshop, National Coal Development Corporation Ltd. at Korba and M.P. Colliery Workers Federation before the Asst. Labour Commissioner (C), Bilaspur in the case of Sri S. K. Bhattacharjee and having regard to the provisions of office order No. CEMW/KB/32/12689-97 dated 12th January, 1970 of the General Superintendent, Central Electrical and Mechanical Workshop, NCDC Ltd. Korba the demand of the Union that Sri S. N. Sinha and such other EP Technicians Gr. III of the said Central Workshop at Korba who were given training by NCDC by a Departmental Training Scheme (Except MTS, MMTI and ITI) should be given the same benefit as S/Sri Banshi Lohar, Ishwar Lohar and Kuldip Singh for fixation in Excavation Grade 'D' (Coal Wage Board) is justified? If so, to what relief they are entitled?

2. *Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.*—(i) Employers: National Coal Development Corporation Limited, Central Electrical and Mechanical Workshop, Korba, P.O. Korba Colliery, Dist. Surguja, M.P.

(ii) Workmen as represented by:

1. M.P. Colliery Worker's Federation P.O: Chirimiri, District Surguja, M.P.

3. *Name of the union if any representing the workmen in question.*—Details given against column (2) above.

4. *Total number of workmen employed in the undertaking affected.*—About 400.

5. *Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.*—46.

We further agree that the decision of the Arbitrators shall be binding on us. In case, the Arbitrators are equally divided in their opinion, the matter shall be referred by them for the decision of Sri R. Sinha, Director (Admn.), National Coal Development Corporation Limited, Ranchi who will function as the Umpire and whose award shall be binding on us.

The Arbitrators or the Umpire, as the case may be, shall make their award within a period of 6 months from the date on which this agreement is published in the Gazette of India or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period mentioned above, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the Parties

(Sd.) I. B. SANYAL, Chief Personnel Officer,
National Coal Development Corporation Limited,
Darbhanga House, Ranchi.

(Sd.) B. N. P. SINHA, Organising Secy.,
M.P. Colliery Workers' Federation,
P.O. Chirimiri, District Surguja, M.P.

(Sd.) SUKHLAL SINGH, Secy.
Madhya Pradesh Colliery Workers' Federation,
P. O. Chirimiri, District Surguja, MP.

Dated at Ranchi, this 7th Day of September 1970

Witnesses:—

1. BRAJ NARAIN PD. 2. P. VENUGOPAL.

[No. 8/180/70-LR.II.]

का० आ० 3856—यतः राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, दरभंगा हाउस रांची की इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल वर्कशाप के प्रबन्धकर्ता से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन, डाकघर चिरिमिरी, जिला सुरगूजा (मध्य प्रदेश) करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः उक्त नियोजकों और उनके कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार

द्वारा उक्त विवाद को उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित कर दिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को एतद्-द्वारा प्रकाशित करती है ।

(करार)

प्रारूप ग

[औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) निगम के नियम 6 के अधीन]

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

करार

पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : 1. श्री आई० बी० सान्याल,
मुख्य कार्मिक अधिकारी,
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड,
दरभंगा हाऊस, रांची ।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : 1. श्री बी० एन० पी० सिन्हा,
संगठन सचिव,
मध्य प्रदेश कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन,
डाकघर चिरिमिरी,
जिला सुरगूजा, मध्य प्रदेश ।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को एतद्द्वारा श्री एम० बी० लवाडे, मुख्य इंजीनियर (ई० एण्ड एम०), राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची और श्री एच० श्रीनिवासन, मुख्य इंजीनियर (एक्सकैवेशन) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है :—

1. विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय : क्या श्री एस० के० भट्टाचार्जी के मामले में सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) बिलासपुर के समक्ष राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, कोर्बा की सेन्ट्रल इलैक्ट्रिकल एण्ड मेकैनिकल वर्कशाप के प्रबन्धतंत्र और एम० पी० कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन के बीच हुए समझौता-ज्ञापन, तारीख 14 जुलाई, 1969 को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, कोर्बा की सैन्ट्रल इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकैनिकल वर्कशाप के जनरल सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय आदेश संख्या सी०ई०एम० डब्ल्यू०/के० बी०/32/12689—97, तारीख 12-1-1970 के उपबन्धों को ध्यान में रखते

	हुए, संघ की यह मांग न्यायोचित है कि उक्त सैन्ट्रल वर्कशाप, कोर्बा के श्री एस०एन०सिन्हा और इसी प्रकार के अन्य ई० पी० टैकनीशियन ग्रेड 3, को जिन्हें राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा विभागीय प्रशिक्षण स्कीम (एम० टी० एस, एम०एम०टी०आई० और आई० टी०आई० के सिवाय) के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया था, एक्सेवेशन ग्रेड 'डी' में (कोला मजदूरी बोर्ड) नियतन के लिये वही फायदा दिया जाना चाहिए जो कि सर्वश्री बंशीलाल लोहार, ईश्वर लोहार और कुलदीप सिंह को दिया गया है? यदि हां, तो वे किस अनुतोष के हकदार हैं ?
2. विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अनुवर्णित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी समिम्लित है ।	(i) नियोजक: राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, सैन्ट्रल इलेक्ट्रिकल एण्ड मकैनिकल वर्कशाप, कोर्बा, डाकघर कोर्बा कोलियरी, जिला सुरगूजा, मध्य प्रदेश । (ii) कर्मकार, जिनका प्रतिनिधित्व एम०पी० कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन, डाकघर चिरिमिरी, जिला सुरगूजा, मध्य प्रदेश करती है ।
3. यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम ।	ऊपर स्तम्भ (2) के सामने ब्यौरा दे दिया गया है ।
4. प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या ।	लगभग 400
5. विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भाव्यत: प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या ।	46

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थों का विनिश्चय हम पर आबद्धकर होगा । यदि मध्यस्थ अपनी राय में बराबर बटे हुए हों, तो उनके द्वारा यह मामला श्री आर० सिन्हा, निदेशक (प्रशासन), राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची के विनिश्चय के लिए निर्देश किया जायगा, जो अधिनिर्णायक के रूप में कार्य करेगा और जिसका पंचाट हम पर आबद्धकर होगा ।

मध्यस्थ या अधिनिर्णायक, जैसी भी स्थिति हो, अपना पंचाट इस करार के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से छः मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा । यदि पंचाट ऊपर वर्णित कालावधि के भीतर

नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निर्देश स्वतः रद्द हो जायेगा और हम नए माध्यस्थम् के लिये बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे ।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

ह०
आई० बी० सान्याल
मुख्य कार्मिक अधिकारी
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड,
दरभंगा हाऊस, रांची ।

ह०
सुखलाल सिंह,
सचिव ।
मध्य प्रदेश कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन,
डाकघर चिरिमिरी,
जिला सुरगूजा, मध्य प्रदेश ।

ह०
बी० एन पी० सिन्हा,
संगठन सचिव ।
एम० पी० कोलियरी वर्कर्स फेडरेशन,
डाकघर चिरिमिरी, जिला सुरगूजा
मध्य प्रदेश ।

रांची, तारीख :
7 सितम्बर, 1970

ह०।.....

ह०।..... [संख्या 8/181/70-एल०आर०-2]

ORDERS

New Delhi, the 22nd October 1970

S.O. 3857.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employer in relation to the management of Messrs. Bolani Ores Limited, Post Office Bolani, Via-Barbil, District Keonjhar and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri B. R. Rao, as Presiding Officer, Industrial Tribunal, with headquarters at Bhubaneshwar and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

(i) Whether there exists in the establishment of Messrs. Bolani Ores Limited, Post Office Bolani, Via-Barbil, District Keonjhar, a sound promotion procedure which is not discriminatory to any of the workmen in their mines?

(ii) Whether the action of the management of Messrs. Bolani Ores Limited, Post Office Bolani, Via Barbil, District Keonjhar, in giving lesser pay to Shri A. K. Mallick and Shri Bacha Singh than Shri Sadanand Roy and Shri Pravakaran is justified? If not, to what reliefs, if any, Shri Mallick and Shri Bacha Singh are entitled?

(iii) Whether the action of the Management of Messrs. Bolani Ores Limited Post Office Bolani, Via-Barbil, District Keonjhar, in fixing higher wages to Shri Dayanidhi Mohanty and nine other workmen at Rs. 190 while fixing the wages as per Wage Board Award as compared to the pay of Rs. 160 fixed in relation to Shri N. K. Samanto, Shri S. K. Ghose, Shri S. K. Sahoo, Shri G. Lakra and Shri H. G. Sahoo, is justified? If not, to what reliefs Shri N. K. Samanto, Shri

S. K. Ghose, Shri S. K. Sahoo, Shri G. Lakra and Shri H. G. Sahoo are entitled?

(iv) Whether Shri D. K. Dubey, a Quarry C Clerk, employed by the management of Messrs. Bolani Ores Limited, Post Office Bolani, Via-Barbil, District Keonjhar, is entitled for the reliefs granted to Shri Balram Nand Keyoliar and Shri Vivekanand, consequent to the promotion of Shri Benjamin Sahoo? If so, from what date?

(v) Whether the management of Messrs. Bolani Ores Limited, Post Office Bolani, Via-Barbil, District Keonjhar, have rightly fixed the wages of Shri M. S. Nair and thirteen other Mechanical Welders and T. M. Helpers? If not, to what reliefs the workmen are entitled?

[No. 10/26/70/LR.IV.]

आदेश

नई दिल्ली, 22 अक्तुबर 1970

का० आ० 3857—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्सबोलानी ओर्स लिमिटेड, डाकघर बोलानी, बारबिल से होकर, जिला कियोंझर के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 क उपधारा (1) क खण्ड (घ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसमें श्री वी० आर० राव, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण के रुप में होंगे जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

(1) क्या मैसर्स बोलानी ओर्स लिमिटेड, डाकघर बोलानी, बारबिल से होकर, जिला कियोन्झर के शासन में प्रोन्नति की ऐसी अच्छी प्रक्रिया विद्यमान है जो उनकी खान में किसी कमकार के प्रति भी भेदभावपूर्ण नहीं है ।

(2) क्या मैसर्स बोलानी ओर्स लिमिटेड, डाकघर बोलानी, बारबिल से होकर, जिला कियोन्झर के प्रबन्धतंत्र की श्री ए०के० मल्लिक और श्री बच्चा सिंह को श्री सदानन्द राय और श्री प्रभाकरन से कम वेतन देने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं तो श्री मल्लिक और श्री बच्चा सिंह किस अनुतोष के यदि कोई हो हकदार है?

(3) क्या मैसर्स बोलानी ओर्स लिमिटेड, डाकघर बोलानी, बारबिल से होकर, जिला कियोन्झर के प्रबन्धतंत्र की मजदूरी बोर्ड के अधिनिर्णय के अनुसार मजदुरी नियत करते समय श्री दयानिधि मोहन्ती और अन्य नौ कर्मकारों की मजदूरी श्री एन० के० समन्तो, श्री एस० के० घोष, श्री एस० के० साहू, श्री जी० लकरा और श्री एच० जी० साहू के सम्बन्ध में नियत 160/रुपये की तुलना में अधिक मजदूरी 190/रु०० नियत करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो एन०के० समन्टो, श्री एस० के० घोष, श्री एस० के० साहु, श्री जी० लकरा और श्री एच० जी० साहू किन अनुतोषों के हकदार हैं ।

(4) क्या मैसर्स बीरानी ओर्स लिमिटेड, डाकघर, बोलानी, बारबिल से होकर, जिला कियोन्झर के प्रबन्धतंत्र द्वारा नियोजित श्री डी० के० बुबे, खदान सी लिपिक उन्हीं अनुतोषों का हकदार है जो श्री बैन्जमिन साहू की प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री बलराम नन्द कियोलियार और श्री विवेकानन्द को दिए गए हैं। यदि हां, तो किस तारीख से ?

(5) क्या मैसर्स बोलानी ओर्स लिमिटेड, डाकघर बोलानी, बारबिल से होकर, जिला कियोन्झर के प्रबन्धतंत्र ने श्री एम० एस० नायर और तेरह अन्य यान्त्रिक खलासियों और टी० एम० मददगारों की मजदूरी ठीक प्रकार से नियत की है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किन अनुतोषों के हकदार है ?

[सं० 10/26/70—एल० आर० 4]

S.O. 3858.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Indian Iron and Steel Company Limited, Gua and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the existing scheme of supply of food grains and the cash value charged in pursuance of the same by the management of Gua and Manoharpur Ore Mines of Indian Iron and Steel Company Limited, Post Gua relating to the workmen employed at Gua and Manoharpur Iron Ore Mines is fair and justified? If not, to what relief the workmen are entitled and from what date?"

[No. 8/22/70/LR-IV.]

का० आ० 3858—अतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में इंडियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, गुआ के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यत: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अत: अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ;

अनुसूची

क्या गुआ और मनोहरपुर लौह अयस्क खानों में नियोजित कर्मकारों के सम्बन्ध में खाद्यान्न प्रदत्त करने की वर्तमान स्कीम और उसके अनुसरण में इंडियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, डाकघर गुआ की गुआ और मनोहरपुर लौह अयस्क खानों के प्रबंधतंत्र द्वारा प्रभारित नकद मूल्य ठीक तथा न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किन अनुतोष के और किस तारीख से हकदार है ?

[सं० फा० 8(22)/70—एल०आर—4]

New Delhi, the 23rd October 1970

S.O. 3859.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Damua Colliery, Kalichhapar Colliery and Damua Hidargarh Siding, and their workmen in respect of the matters specified in the schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the management of Damua Colliery, Kalichhapar Colliery and Damua Hidargarh Siding belonging to Messrs Kanhan Valley Coal Company Private Limited, Messrs. C. P. Syndicate Private Limited and Messrs Byramji Mining Combined Private Limited respectively is justified in not paying—

(i) Difference of wages from the 15th August, 1967 to the 12th November, 1967;

(ii) Variable Dearness Allowance as per Wage Board Recommendations at the rates of Rs. 1.11 per day from the 1st October, 1967, Rs. 1.47 per day from the 1st April, 1968 and Rs. 1.29 per day from the 1st October, 1969;

(iii) Other benefits in accordance with the recommendations of the Central Wage Board for Coal Mining Industry as accepted by the Government of India in their Resolution No. WB-16(5)|66, dated the 21st July, 1967.

If not, to what relief are the workmen entitled?"

[No. 1|3|70-LRII.]

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर 1970

का० आ० 3859.—अतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स दमुआ कोलियरी, कालीछप्पर कोलियारी और दमुआ हीदरगढ़ साइडिंग के प्रबन्धतंत्रों से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय करती है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7—क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स कान्हन वेली कौल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स सी० पी० सिन्डीकेट प्राइवेट लिमिटेड, और मैसर्स बीरमजी माइनिंग कम्बाइन्ड प्राइवेट लिमिटेड की क्रमशः दमुआ कोलियारी, कालीछप्पर कोलियारी और दमुआ हीदरगढ़ साइडिंग के प्रबन्धतंत्र का निम्नलिखित को संदाय न करना न्यायोचित है :—

(1) 15 अगस्त, 1967 से 12 नवम्बर, 1967 तक की मजदूरी का अन्तर;

(2) मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार प्रथम अक्टूबर, 1967 से 1.11 रु० प्रतिदिन, प्रथम अप्रैल, 1968 से 1.47 रु० प्रतिदिन और प्रथम अक्टूबर, 1969 से 1.29 रु० प्रतिदिन की दर से परिवर्तनीय महंगाई भत्ता ;

(III) भारत सरकार द्वारा अपने संकल्प सं० डब्ल्यू बी–16(5)/66 तारीख 21 जुलाई, 1967 में यथा प्रतिगृहित केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड के कोयलाखनन उद्योग के लिए की गई सिफारिशों के अनुसार अन्य फायदे ।

यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

[सं० 1/3/70–एल० आर० II]

New Delhi, the 28th October 1970

S.O. 3860.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bansdeopur Colliery of Messrs New Bansdeopur Colliery (Private) Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bansdeopur Colliery of Messrs New Bansdeopur Colliery (Private) Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad, in refusing employment to Shri Narbahadur, Night Guard, with effect from the 2nd January, 1970 was justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

[No. 2/123/70-LR.II.]

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1970

का० आ० 3860.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मेसर्स न्यू बन्सदेवपुर कौलियरी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर कुसुन्दा, जिला धनबाद की बन्सदेवपुर कोयला खान के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं० 2), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मेसर्स न्यू बन्सदेवपुर कोलियरी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर कुसुन्दा, जिला धनबाद की बन्सदेवपुर कोयला खान के प्रबन्धतंत्र की श्री नरबहादुर, रात के पहरेदार को 2 जनवरी, 1970 से नियोजित करने से इन्कार करने की कार्यवाही न्यायोचित थी ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

[सं० 2/123/70 एल० आर० II]

S.O. 3861.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Jamadoba, Post Office Jealgora, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it dsirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, (No. 2) Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Jamadoba, Post Office Jealgora, District Dhanbad in dismissing Shri A. Kumar, Overman from service with effect from the 19th November, 1969, is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

[No. 2/143/70-LRII.]

का० आ० 3861.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, जामादोबा, डाकघर जीलगौरा, जिला धनबाद की जामादोबा कालियरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निदेशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 2) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स टाटा आयरन एन्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, जामादोबा, डाकघर जीलगौरा, जिला धनबाद की जामादोबा कालियरी के प्रबन्धतंत्र की श्री ए० कुमार, ओवरमैन को 19 नवम्बर, 1969 से नौकरी से पदच्युत करने की कार्यवाही न्यायोचित थी ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० 2/143/70-एल आर-2]

S.O. 3862.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Damoda Colliery, Post Office Raniganj, District Burdwan-4 and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Keeping in view the recommendations of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry as accepted by the Government of India in their Resolution No. WB-16(5)/66, dated 21st July, 1967 and having regard

to the financial capacity, whether the management of Damoda Colliery of Messrs Damoda Coal Company Private Limited, Post Office Raniganj, District Burdwan, was justified in paying Variable Dearness Allowance at the rate of Rs. 0.78 paise per head per day during the period from 1st October, 1967 to 3rd August 1969 to weekly paid workers, and from 1st October 1967 to 31st July 1969 to monthly paid staff and at the rate of Rs. 1.11 paise per head per day from 4th August 1969 to 30th September 1969 to weekly paid workers, from 1st August, 1969 to 30th September 1969 to monthly paid staff, instead of Rs. 1.11 paise per had per day from 1st October 1967 to 31st March, 1968 and at the rate of Rs. 1.47 paise per head per day from 1st April 1968 to 30th September 1969 and Variable Dearness Allowance at the rate of Rs. 1.29 paise per head per day from 1st April, 1970 instead of at the rate of Rs. 1.53 paise per head per day to all workers, first annual increment to the weekly paid workers and monthly paid staff from 28th April 1969 and 1st May, 1969 respectively instead of from 15th August 1968, second annual increment to weekly paid workers from 12th October 1969 and monthly paid staff from 1st October 1969 instead of 15th August 1969 and sick leave wages from 1st January, 1969 instead of from 15th August 1967 to all workers?

If not, to what relief are the workmen entitled?"

[No. 6/54/70-LR.II.]

का० आ० 3862.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में दामोदा कालियरी, डाकघर, रानीगंज, जिला बर्दवान-4 के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और, यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"भारत सरकार द्वारा अपने संकल्प संख्या वे०-बो०-16(5)166, दिनांक 21 जुलाई, 1967 में यथास्वीकृत कोयला खान उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों तथा वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए, क्या मैसर्स दामोदा कोल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, डाकघर, रानीगंज, जिला बर्दवान की दामोदा कालियरी के प्रबन्धतंत्र का साप्ताहिक मजूरी प्राप्त करने वाली श्रमिकों को 1-10-1967 से 3-8-1969 की अवधि में और मासिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 1-10-1967 से 31-7-1969 की अवधि में 78 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर तथा साप्ताहिक मजूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों को 4-8-1969 से 30-9-1969 तक और मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 1-8-1969 से 30-9-1969 तक 1.11 रु० प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से परिवर्ती महंगाई भत्ता देना, जब कि उन्हें यह भत्ता 1-10-1967 से 31-3-1968 तक 1.11 रु० प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और 1-4-1968 से 30-9-1969 तक 1.47 रु० प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से दिया जाना चाहिए था, सभी श्रमिकों को 1-4-1970 से 1.53 रु० प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के स्थान पर 1.29 रु० प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से परिवर्ती महंगाई भत्ता देना, साप्ताहिक मजूरी पाने वाले श्रमिकों तथा मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को पहली वार्षिक वेतन-वृद्धि 15-8-1969 के स्थान पर क्रमशः 28-4-1969 और 1-5-1969 से देना, साप्ताहिक मजूरी पाने वाले श्रमिकों त.. मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दूसरी वेतन-वृद्धि 15-8-1969 के स्थान पर क्रमशः 12-10-6

और 1-10-1960 से देना और सभी श्रमिकों को बीमारी छुट्टी की मंजूरी 16-8-1967 के स्थान पर 1-1-1969 से देना न्यायोचित था ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[सं० 6/54/70-एल० आर०-2]

New Delhi, the 30th October 1970

S.O. 3863.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Amlabad Colliery of Messrs Bhowra Kankanee Collieries Limited, Post Office Bhowra (Dhanbad) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2) Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the transfer of Shri Bindeswar Mahato, Onsetter from Amlabad Colliery of Messrs Bhowra Kankanee Collieries Limited, Post Office Bhowra (Dhanbad) to Madhuband Colliery of Messrs Oriental Coal Company Limited, Post Office Nudkhurkee (Dhanbad) with effect from the 25th April, 1970 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

[No. 2/113/70-LRII.]

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1970

का० आ० 3863.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भोरा कंपनी कोलियरीज लिमिटेड, डाकघर भोरा (धनबाद) की अमलाबाद कोयला खान के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं० 2), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या श्री बिन्देश्वर महतो, अनसैटर का मैसर्स भोरा कंकानी कोलियरीज लिमिटेड, डाकघर भोरा (धनबाद) की अमलाबाद कोयला खान से मैसर्स ओरिएण्टल कोल कंपनी लिमिटेड, डाकघर नुदखुर्की (धनबाद) की मधुबन्द कोयला खान को 25 अप्रैल 1970 से अन्तरण किया जाना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० 2/113/70 एल० आर० II]

New Delhi, the 6th November 1970

S.O 3864.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Ballarpur Colliery of Messrs Ballarpur Collieries Company Limited, Post Office Ballarpur,

District Chandrapur, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Ballarpur Colliery belonging to Messrs Ballarpur Colliery Company, Ballarpur, District Chandrapura in dismissing Shri Chedhoo son of Hamid, Badli workman, with effect from the 23rd June, 1970 is justified? If not, to what relief is he entitled?"

[No. 5/15/70-LR.II.]

नई दिल्ली, 6 नवम्बर 1970

का० आ० 3864.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मेसर्स बल्लरपुर कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, डाकघर बल्लरपुर, जिला चन्द्रपुर की बल्लरपुर कोयलाखान के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा (7क) के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मेसर्स बल्लरपुर कोलियरीज कंपनी बल्लरपुर, जिला चन्दनपुर की बल्लरपुर कोयला खान के प्रबन्धतंत्र की श्री चेद् सुपुत्र हमीद बदली कर्मकार को 23 जून, 1970 से पदच्युत करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो वह किसी अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० 5/15/70 एल० आर०2]

S.O. 3865.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Pure Kustore Colliery of Messrs Pure Kustore Collieries Company Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2) Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Pure Kustore Colliery of Messrs Pure Kustore Collieries Company Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad, in terminating the services of Shri Madheshwar Singh, Night Guard, with effect from the 6th November, 1967, was justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

[No. 2/121/68-LR.II.]

का० आ० 3865.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स प्योर कुस्तोर कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड डाकघर कुसुन्डा, जिला धनबाद की प्योर कुस्तोर कोयला खान के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है –

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं० 2), धनाबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स प्योर कुस्तोर कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड डाकघर कुसुन्डा, जिला धनबाद की प्योर कुस्तोर कोयलाखान के प्रबन्धतंत्र की श्री मधेश्वर सिंह, रात के पहरेदार की सेवाओं को 6 नवम्बर 1967, से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित थी ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० 2/121/68-एल० आर० 2]

S.O. 3866.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Burragarh Colliery of Messrs Raneegunge Coal Association Limited, Post Office Kustore, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2) Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the loaders of 3 Pit, 11 Seam of Burragarh Colliery of Messrs Raneegunge Coal Association Limited, Post Office Kustore, District Dhanbad, went on strike in second shift of the 8th April, 1970? If not, to what relief are they entitled?"

[No. 2/108/70-LRII.]

का० आ० 3866.—यतःकेन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स रानीगंज कोल एसोसिएशन लिमिटेड डाकघर कुस्तोर, जिला धनबाद की बुरागढ़ कोयला खान के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं० 2), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मसर्स रानीगंज कोल एसोसिएशन लिमिटेड डाकघर कुस्तोर, जिल. धनबाद की बुर्रागढ़ कोयला खान के 3 मर्तों 11 सीमों के लीडरों ने 8 अप्रल, 1970 की दूसरी प.री में हड़ताल की थी ? यदि नहीं तो व किस अनुतोष के हटकदार है ?

[सं० 2/108/70 एल० आर० 2]

New Delhi, the 10th November 1970

S.O. 3867.—Whereas the employers in relation to the management of Kedla Jharkhand Collieries, Post Office Kedla, District Hazaribagh and their workmen represented by Koyala Shramik Sangathan, Post Office Kedla, District Hazaribagh have jointly applied to the Central Government under sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) for reference of an industrial dispute that exists between them to an Industrial Tribunal in respect of the matters set forth in the said application and reproduced in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government is satisfied that the persons applying represent the majority of each party;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the management of the Kedla Colliery is justified in retrenching the services of Sri Yakub Toppo, Mechanic of the Colliery; if not, to what relief is he entitled and from what date?"

[No. 8/170/70-LRII.]

नई दिल्ली, 10 नवम्बर 1970

का० आ० 3867.—यतः केदला झारखंड कौलियरीज, डाकघर केदला, जिला हजारीबाग के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों, जिनका प्रतिनिधित्व कोयला श्रमिक संगठन डाकघर केदला, जिला हजारीबाग करता है, ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन संयुक्त रूप से केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है कि वह उनके बीच विद्यमान औद्योगिक विवाद को उक्त आवेदन में उपवर्णित और इससे उपाबद्ध अनुसूची में उद्धृत विषयों के बारे में किसी औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित करे ;

और यत : केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्षकार के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं ;

अत :, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (संख्या 2), धनबाद, को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या केदला कालियरी के प्रबन्धतंत्र का कोलियरी के मेकैनिक, श्री याकूब टोप्पो की सेवा से छंटनी करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो वह किस अनुतोष का और किस तारीख से हकदार है ?"

[सं० 8/170/70-एल० आर०-2]

S.O. 3868.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Digwadih Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Jamadoba, Post Office Jealgora, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, (No. 2) Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Digwadih Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Jamadoba, Post Office Jealgora, District Dhanbad, in terminating the lien on permanent employment of Shri Bikau Pandey, Piece rated Trammer, with effect from the 31st, December, 1969, and placing his name in the badli list from the same date was justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

[No. 2/120/70-LRII.]

का० आ० 3868.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड, जामादोबा, डाकघर जीलगोरा, जिला धनबाद की डिग्वाडीह कौलियरी से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निदर्शित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (संख्या 2), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ?

अनुसूची

"क्या मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड, जामादोबा, डाकघर जीलगोरा, जिला धनबाद की डिग्वाडीह कॉलियरी के प्रबंधतंत्र की 31 दिसम्बर, 1969 से श्री बीकु पांडे, मात्रानुपाती दर वाले ट्रैमर का स्थायी नियोजन पर धारणाधिकार समाप्त करने और उसी तारीख से उसका नाम बदली सूची में रखने की कार्यवाही न्यायोचित थी ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० 2/120/70-एल० आर०-2]

S.O. 3869.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Victoria West Colliery, Post Office Dishergarh, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the management of Victoria West Colliery of Messrs New Birbhum Coal Company Limited, Post Office Barakar, District Burdwan is justified in denying payment of wages for paid holidays to Sarvashri Dasarath Pasman, Moti Nunia and Amrit Pasman, Sardars? If not to what relief are these workmen entitled and from what date?"

[No. 6/59/70-LRII.]

का० आ० 3869.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में विक्टोरिया वैस्ट कोलियरी, डाकघर दिशेरगढ़, जिला बर्दवान के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और, यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अत :, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता, को न्यायानिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स न्यु बिरभूम कौल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर बाराकार, जिला बर्दमान की विक्टोरिया वैस्ट कोलियरी के प्रबन्धतंत्र का सर्वश्री दसरथ पासमान, मोती नुनिया और अमृत पासमान, सरदारों को सदाय सहित छुट्टियों की मजदूरी देने से इन्कार करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो ये कर्मकार किस अनुतोष के और किस तारीख से हकदार हैं ?"

[सं० 6/59/70-एल आर० 2]

S.O. 3870.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Manoharbahal Colliery, Post Office Asansol, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the management of Manoharbahal Colliery of Messrs Rai Sahib Chandumul Indrakumar Karnani Private Limited, Post Office Asansol,

District Burdwan was justified in stopping from work Sarvashri Kishan Bhar, Baejoo Jaswara, Ramawedh Harijan, Suraj Harijan, Kariya Harijan, Ramchij Harijan, Rambanam Bahar, Sampat Bhar, Sadafal Harijan and Chandeo Bhar, Loaders of Monoharbahal Colliery without notice from the 8th August, 1970? If not, to what relief these workmen are entitled?"

[No. 6/63/70-LRII.]

का० आ० 3870—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मनोहरबहल कोलियरी, डाकघर आसनसोल, जिला वर्दमान के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता, को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स राय साहिब चन्दुमल इन्द्रकुमार करनानी प्राइवेट लिमिटेड, डाकघर आसनसोल, जिला वर्दमान की मनोहरबहल कोलियरी के प्रबंधतंत्र का सर्वश्री किशन भार, बैजू जसवारा, राम अवध हरिजन, सूरज हरिजन, करिया हरिजन, रामचीज हरिजन, रामबनम भार, सम्पत भार, सदाफल हरिजन और चन्देश्रो भार, मनोहरबहल कोलियरी के लीडरों को बिना नोटिस के 8 अगस्त, 1970 से काम से हटाना न्यायोचित था ? यदि नहीं, तो ये कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

[सं० 6/63/70-एल० आर० 2]

New Delhi, the 18th November 1970

S.O. 3871.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists among the management of Messrs Mineral Sales (Private) Limited, Mine Owners Hospet, their Contractors in Vyasanakere Iron Ore Mine and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it dsirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri B. M. Jayamahadeva as Presiding Officer with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

1. "Whether the management of Messrs. Minerals Sales (P) Limited, Mine Owners, Hospet or their contractors are responsible to implement the recommendations of the Central Wage Board for Iron Ore Mining Industry to the piece-rated workmen, employed in the Vyasanakere Iron Ore Mine, Vyasanakere, Hospet? To what relief, if any, are the workmen entitled?"

[No. 10(42)/70-LR-IV.]

नई दिल्ली, 18 नवम्बर 1970

का० आ० 3871.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स मिनरल सेल्स (प्राइवेट लिमिटेड) माइन ओनर्स होस्पेट के प्रबन्धतंत्र, व्यासंकेरे आयरन ओर माइन में उनके ठेकेदारों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी० एन० नारायण रेड्डी, जिनका मुख्यालय बैंगलौर होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

1. क्या मैसर्स मिनरल्स सेल्स (प्रा०) लि०, माइन ओनर्स, होस्पेट का प्रबन्धतंत्र अथवा उनके ठेकेदार व्यासंकेरे आयरन ओर माइन, व्यासंकेरे, होस्पेट में नियोजित मात्रानुपाती दर के कर्मकारों पर लोह अयस्क खान उद्योग के लिए केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी हैं? कर्मकार किस अनुतोष के, यदि कोई हों, हकदार हैं।

[सं० 10(42)/70/एल० आर०-4]

New Delhi, the 20th November 1970

S.O. 3872.—Whereas, the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Singareni Collieries Company Limited, Post Office Kothagudem Collieries (Andhra Pradesh) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri T. Chandrasekharar Reddy, as Presiding Officer with headquarters at Afzal Lodge, Tilak Road, Ramkote, Hyderabad-1, and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the management of Singareni Collieries Company Limited. Belampalli was justified in suspending Sarvashri Shaik Mohammed, P. Ramuloo and Gengadhar, Fitters, Engineering Department, Belampa.. Division with effect from the twenty-seventh May, 1969 for 10 days without wages If not, to what relief are these workmen entitled?"

[No. 7/3/70-LR.II.]

P. C. MISRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 नवम्बर 1970

का० आ० 3872—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सिंग्रेनी कोलियरीज कम्पनी, लिमिटेड, डाकघर कोठागूडम कोलियरीज (आन्ध्र प्रदेश) के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यत: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अत: अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० चन्द्रशेखर रेड्डी होंगे जिनका मुख्यालय अफजल लॉज, तिलक रोड, रामकोट, हैदराबाद-1 होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, बेलमपल्ली के प्रबन्धतंत्र का सर्व श्री शेख मोहम्मद, पी० रामुलू और गंगाधर, फिटार्स, इंजीनियरी विभाग, बेलमपल्ली डिवीजन को 27 मई, 1969 से 10 दिन के लिए बिना मजदूरी के निलम्बित करना न्यायोचित था? यदि नहीं तो ये कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

[सं० 7/3/70-एल० आर० II]

पि० सी० मिश्र अवर सचिव ।

(Department of Labour & Employment)

(Office of the Chief Labour Commissioner, Central)

ORDERS

New Delhi, the 13th October 1970

S.O. 3873.—Whereas an application has been made under section 19(b) of the Payment of Bonus Act, 1965 by Messrs Travancore Titanium Products Ltd., (employer) in relation to their establishments mentioned in the Schedule below for extension of the period for the payment of bonus to their employees for the accounting year ending on 31st December, 1969.

And whereas being satisfied that there are sufficient reasons to extend the time I have, in exercise of the powers conferred on me by the proviso to clause (b) of Section 19 of the said Act read with the notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Employment No. WB-20(42)/65 dated the 28th August, 1965, passed orders on 8th October, 1970 extending the period for payment of the said bonus by the said employer by one months (i.e. upto 30th September, 1970) from the last date for payment of bonus under clause (b) of Section 19 of the Act.

Now this is published for information of the employer and all the employees of the said establishment.

THE SCHEDULE

Name and address of the employer(s)	Establishment(s).
M/s. Travancore Titanium Products Ltd., Kochu veli, P. B. No.—1, *Trivandrum*—21 (Kerala).	

[No. BA-6(10)/70-LS-I.]

श्रम और रोजगार विभाग

मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली 13 अक्टूबर 1970

एस० ओ० 3873—यत: मेसर्स ट्रैवनकोर टिटैनियम लि० (नियोजक) ने नीचे की अनुसूची में वर्णित अपने स्थापनों के संबंध में 31.12.69 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों को बोनस के संदाय की कालावधि को बढ़ाने के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 19(ख) के अधीन आवेदन दिया है।

और यत: यह समाधान हो जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण है, मैंने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० डब्ल्यू बी–20 (42)/65 तारीख 28 अगस्त, 1965 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 के खंड (ख) के परन्तुक द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 8.10.70 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त बोनस के संदाय की कालावधि को अधिनियम की धारा 10 के खंड (ख) के अधीन बोनस के संदाय की अंतिम तारीख से———महिने (अर्थात् 30.9.70 तक) बढ़ाने का आदेश दे दिया है।

अब इसे उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

अनुसूची

नियोजक/नियोजकों का नाम और पता	स्थापन
मेसर्स ट्रैवनकोर टिटैनियम प्रोडक्टस लि० कोचू वेली, पी.बी.न. 1, त्रिवेन्द्रम-21 (केरल)	

(ओ० वेंकटाचलम)

सं० बी.ए. 6(10) 70–एल. एस–I)

New Delhi, the 15th October 1970

S.O. 3874.—Whereas an application has been made under section 19(b) of the Payment of Bonus Act, 1965 by Messrs Pure Jambad Collieries (P) Ltd. (employer) in relation to their establishments mentioned in the Schedule below for extension of the period for the payment of bonus to their employees for the ...ting year ending on 31st December, 1969.

And whereas being satisfied that there are sufficient reasons to extend the time I have, in exercise of the powers conferred on me by the proviso to clause (b) of Section 19 of the said Act read with the notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Employment No. WB-20(42)/65 dated the 28th August, 1965, passed orders on 12th October, 1970 extending the period for payment of said bonus by the said employer by three months (i.e. upto 30th November, 1970) from the last date for payment of bonus under clause (b) of Section 19 of the Act.

Now this is published for information of the employer and all the employees of the said establishment.

The Schedule

Name and address of the employer(s).	Establishment(s).
M/s. Pure Jambad Collieries Private Ltd 135, Biplabi Rash Behari Basu Road, Calcutta—1.	Pure Jambad Colliery, P. O. Kajoragram, Distt. Burdwan.

[No. BA-5(12)/70-LS-I.]

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर 1970

एस० ओ० 3874—यत: मैसर्स प्योर जम्बाद कोइलरी (प्रा०) लि० (नियोजक) ने नीचे की अनुसूची में वर्णित अपने स्थापनों के संबंध में 31.12.1969 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों को बोनस के संदाय की कालावधि को बढ़ाने के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 19(ख) के अधीन आवदन दिया है।

और यत: यह समाधान हो जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण है, मैंने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० डब्ल्यू बी–20 (42)/65 तारीख 28 अगस्त, 1965 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 के खंड (ख) के परन्तुक द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12.10.70 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त बोनस के संदाय की कालावधि को अधिनियम की धारा 19 के खंड (ख) के अधीन बोनस के संदाय को अंतिम तारीख से 3 महिने (अर्थात् 30.11.1970 तक) बढ़ाने का आदेश दे दिया है।

अब इसे उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

अनुसूची

नियोजक/नियोजकों का नाम और पता	स्थापन
मैसर्स प्योर जम्बाद कोइलरी (प्रा०) लि० 135, बीपलाबी रास बिहारी बसु रोड, कलकत्ता–1	प्योर जम्बाद कोइलरी, पो० ओ० कजोरा ग्राम जिला वर्धमान

(ओ० वेंकटाचलम)
मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)

[सं० बी.ए. 5 (12)/70–एम० एस०]

New Delhi, the 17th October 1970

S.O. 3875.—Whereas an application has been made under Section 19(b) of the Payment of Bonus Act, 1965 by Messrs Lodha Colliery Company (1920) Ltd., (employer) in relation to their establishments mentioned in the Schedule below for extension of the period for the payment of bonus to their employees for the accounting year ending on 31st December, 1969.

And whereas being satisfied that there are sufficient reasons to extend the time I have, in exercise of the powers conferred on me by the proviso to clause (b) of Section 19 of the said Act read with the notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Employment No. WB-20(42)/65 dated the 28th

August, 1965, passed orders on 15th October, 1970 extending the period for payment of the said Bonus by the said employer by three months (i.e. up to 30th November, 1970) from the last date for payment of bonus under clause (b) of Section 19 of the Act.

Now this is published for information of the employer and all the employees of the said establishment.

THE SCHEDULE

Name and address of the employer(s).	Establishment(s).
M/s. Lodna Colliery Company (1920) Ltd., Jharia, E. Rly.	Lodna, & Bagdigi collieries Lodna Coke Plant, P. O. Jharia Dhanbad. Sripur Colliery and Nengah Colliery and Rana Collieries, S. S. Incline collieries, P. O. Kalipahari, Burdwan.

[No. BA-6(16)/70-LS.I.]

नई दिल्ली, 17 नवम्बर 1970

एस० ओ० 3875—यत : मेसर्स लोधना कौलरी कम्पनी (1920) लिमिटेड (नियोजक) ने नीचे की अनुसूची में वर्णित अपने स्थापनों के संबंध में 31.12.69 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों को बोनस के संदाय की कालावधि को बढ़ाने के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 19(ख) के अधीन आवेदन दिया है।

और यत: यह समाधान हो जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण है, मैंने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० डब्ल्यू बी–20(42)/65 तारीख 28 अगस्त, 1965 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 के खंड (ख) के परन्तुक द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15-10-1970 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त बोनस के संदाय की कालावधि को अधिनियम की धारा 19 के खंड (ख) के अधीन बोनस के संदाय की अंतिम तारीख से 3 महीने (अर्थात 30.11.1970 तक) बढ़ाने का आदेश दे दिया है।

अब इसे उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों को सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

अनुसूची

नियोजक/नियोजकों का नाम और पता	स्थापन
मेसर्स लोधना कौलरी कम्पनी (1920) लिमिटेड, झरिया, ई : रेलवे।	लोधना और बागदिगी कौलरीज लोधना कोक प्लॉट, झरिया पो० आ० धनबाद।

(ओ० वेंकटाचलम)]
मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)

[सं० बी० ए० 6 (16)/70 एल० एस०]

New Delhi, the 28th October 1970

S.O. 3876.—Whereas an application has been made under section 19(b) of the Payment of Bonus Act, 1965, by Messrs New Jemehari Khas Colliery (Private) Ltd. (employer) in relation to their establishments mentioned in the Schedule below for extension of the period for the payment of bonus to their employees for the accounting year ending on 31st December, 1969.

And whereas being satisfied that there are sufficient reasons to extend the time I have, in exercise of the powers conferred on me by the proviso to clause (b) of Section 19 of the said Act read with the notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Employment No. WB-20(42)|65, dated the 28th August, 1965, passed orders on 26th October, 1970, extending the period for payment of the said bonus by the said employer by two months (i.e. upto 31st October, 1970), from the last date for payment of bonus under clause (b) of Section 19 of the Act.

Now this is published for information of the employer and all the employees of the said establishment.

THE SCHEDULE

Name and address of the employer(s)	Establishment(s)
M|s. New Jemehari Khas Colliery (Private) Ltd., P.O. Searsole Rajbari (Burdwan).	New Jemehari Khas Colliery, P.O. Jaykaynagar, Dist. Burdwan.

[No. BA-5(13)/70-LS.I.]

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर 1970

एस० ओ० 3876—यतः मैसर्स न्यू जमेरी खास कोलीयरी प्रा० लि० (नियोजक) के नीचे की अनुसूची में वर्णित अपने स्थापनों के संबंध में 31-12-69 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों को बोनस के संदाय की कालावधि को बढ़ाने के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 19(ख) के अधीन आवेदन दिया है ।

और यतः यह समाधान हो जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण है, मैंने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० डब्ल्यू बी-20(42/65 तारीख 28 अगस्त, 1965 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26-10-70 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त बोनस के संदाय की कालावधि को अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के अधीन बोनस के संदाय को अंतिम तारीख से 2 महिने (अर्थात् 31-10-70 तक) बढ़ाने का आदेश दे दिया है ।

अब इसे उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

अनुसूची

नियोजक/नियोजकों का नाम और पता	स्थापना
मेसर्स न्यू जमेरी खास कौलियरी (प्रा०) लि० पो०ओ० सीरसोल राज बारी (बर्द्धवान)	न्यू जमेरी कौलियरी, पो० ओ० जे० के० नगर (बर्द्धवान)

[सं० बी०ए० 65(13)/70-एल०एस० आई०]

New Delhi, the 21st November 1970

S.O. 3877.—Whereas an application has been made under section 19(b) of the Payment of Bonus Act, 1965 by Messrs Shree Shree Lakshmi Narain Trust (employer) in relation to their establishments mentioned in the Schedule below for extension of the period for the payment of bonus to their employees for the accounting year ending on 31st December, 1969.

And whereas being satisfied that there are sufficient reasons to extend the time I have, in exercise of the powers conferred on me by the proviso to clause (b) of Section 19 of the said Act read with the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. WB. 20(42)/65 dated the 28th August, 1965 passed order on 19th November, 1970 extending the period for payment of the said bonus by the said employer by three months (i.e. up to 30th November, 1970) from the last date for payment of bonus under clause (b) of Section 19 of the Act.

Now this is published for information of the employer and all the employees of the said establishment.

THE SCHEDULE

Name and address of the employer (S)	Establishment (S)
Shree Shree Lakshmi Narain Trust, East Kumardhubi Colliery, P. O. Chirkunda, Dhanbad.	

[No. BA-5(17)/70-LS.I.]
O. VENKATACHALAM, Chief Labour Com.

दई दिल्ली, 21 नवम्बर 1970

एस० ओ० 3877—यतः मेसर्स श्री श्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट (नियोजक) ने नीचे की अनुसूची में वर्णित अपने स्थापनों के संबंध में 31-12-1969 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों को बोनस के संदाय की कालावधि को बढ़ाने के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 19(ख) के अधीन आवेदन दिया है।

और यत: यह समाधान हो जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण है, मैंने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० डब्ल्यू बी—20(42)/65 तारीख 28 अगस्त, 1965 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19-11-70 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त बोनस के संदाय की कालावधि को अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के अधीन बोनस के संदाय को अंतिम तारीख से 3 महीने (अर्थात् 30-11-70 तक) बढ़ाने का आदेश दे दिया है।

अब इसे उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

अनुसूची

नियोजक/नियोजकों का नाम और पता	स्थापन
श्री श्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट, ईस्ट कुमारधुबी कोलरी, पी० ओ० चिरकुंडा, धनबाद, बिहार।	

[सं० बी० ए० 5(17)/70 एल० एस०-1]

ओ० वेंकटाचलम,
मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)।

(Department of Rehabilitation)
(Office of the Chief Settlement Commissioner)

New Delhi, the 19th November 1970

S.O. 3878.—In exercise of the powers conferred on the Chief Settlement Commissioner by Section 34(2) of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) he hereby delegates to the Deputy Secretary in the Rehabilitation Department of the Punjab State exercising the powers of Settlement Commissioner, his powers under Section 30(2) of the said Act for the purpose of passing necessary orders under this Section in respect of acquired evacuee properties forming part of the compensation pool.

[No. 3(25)/LR/70.]

W. G. PATHAK, Chief Settlement Com.

(पुनर्वास विभाग)

मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1970

एस० ओ० 3878.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 (1954 का 44) की धारा 34(2) द्वारा मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वे एतद्द्वारा पंजाब सरकार के पुनर्वास विभाग में बन्दोबस्त आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने वाले उप सचिव को उक्त अधिनियम की धारा के अन्तर्गत अर्जित निष्क्रान्त सम्पत्तियों के जो मुआवजा पूल का एक अंग हो, संबंध में इस धारा के अन्तर्गत आवश्यक आदेश देने के लिए अपने अधिकार सौंपते हैं।

[सं० 3(25)/एल० आर०/70]

वा० ग० पाठक मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त

MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES
[Cultural Activities Division I]
CAI(I) Section

New Delhi, the 16th November 1970

S.O. 3879.—The following draft of certain rules further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), is hereby published, as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 26th December 1970.

Any objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft before the date so specified will be taken into consideration by the Central Government. Such objections or suggestions should be addressed to Shri A. S. Talwar, Under Secretary, Ministry of Education and Youth Services, Shastri Bhavan, New Delhi.

Draft Rules

1. These rules may be called the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Rules, 1970.

2. In rule 8 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959 for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:

"(d) hawk or sell any goods or wares or canvas any custom for such goods or wares or display any advertisement in any form or show a visitor round or take his photograph for monetary consideration, except under the authority of, or under, and in accordance with the conditions of, a licence granted by an archaeological officer; or".

[No. F. 5/51/69-CAI(1).]

A. S. TALWAR, Under Secy.

शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय

(सी ए (I) अनुभाग)

नई दिल्ली 16 नवम्बर, 1970

एस० ओ० 3879.—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जो केन्द्रीय सरकार प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष से अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार इससे सम्भावयतः प्रभावित होनेवाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर 26 दिसम्बर, 1970 को या के पश्चात् विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति, से, इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व, जो आक्षेप या सुझाव प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। ऐसे आक्षेप या सुझाव श्री ए० एस० तलवार, अवर सचिव, शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली, को भेजे जाने चाहिए।

प्रारूप नियम

1. ये नियम प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

2. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 के नियम 8 में खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) किसी पुरातत्वीय अधिकारी के प्राधिकार के अधीन, या उसके द्वारा मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन और अनुसार के सिवाय, किसी माल या भाण्डों की फेरी या बिक्री या ऐसे माल या भाण्डा के लिए गाहकी की प्रायचना या किसी रूप में विज्ञापन का संप्रदर्शन नहीं करेगा या धन के रूप में प्रतिफल के लिए किसी दर्शक को चारों ओर दिखाने के लिए नहीं ले जाएगा या उसका फोटो नहीं लेगा ; या"।

[एफ० सं० 5/51/69—सी० ए०/1(1)]

ए० एस० तलवार,
अवर सचिव, भारत सरकार।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970